प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती, जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

वर्ष-08, अंक - 42 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 06 अगस्त 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

दतिया उप चुनाव परिणाम के मायने...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

हर चुनाव कोई न कोई संदेश अवश्य देता है। हाल ही में दतिया विधानसभा उपचुनाव के किसी भी परिणाम से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला था। लेकिन इस उप चुनाव में सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के हारने पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है, यहां कांग्रेस की जीत से ज्यादा भाजपा की हार के चर्चे हैं। प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव परिणाम तक भाजपा के लिए कुछ भी ठीक नहीं रहा। भाजपा दावा करती है कि, वो कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं की राय को महत्वपूर्ण माना जाता है, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और किसी भी निर्णय की अंतिम कसौटी संगठन और कार्यकर्ता ही है। लेकिन दतिया उप चुनाव में टिकट के लिए प्रदेश संगठन ने केवल एक नाम नरोत्तम मिश्रा का भेजा था, ऐसा भाजपा के सूत्रों के हवाले से ही खबर आई थी। लेकिन बावजूद इसके हाई कमान ने पूर्व गृहमंत्री का टिकट काटकर संघ पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति को टिकट दे दिया। जिसके बाद दतिया में बवाल हुआ और पार्टी के जिलाध्यक्ष तक ने त्यागपत्र की पेशकश कर दी थी। भाजपा की डेमेज कंट्रोल टीम सक्रिय हुई और नरोत्तम मिश्रा को साथ लेकर तत्काल मामला सुलझाने का दावा किया गया जो केवल तात्कालिक ही साबित हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पैराशुट प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया और डबल इजंन की सरकार के साथ तमाम मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारीयो के व्यापक प्रचार के बावजूद यह सीट भाजपा नहीं जीत सकी। जिसके बाद कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि, सत्ता परिवर्तन का शंखनाद दतिया से प्रारंभ हो चुका है और मोहन सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है।

इस चुनाव की एक और यह विशेषता रही कि, दोनों ही दलों में वर्तमान उम्मीद्वार से ज्यादा 2023 में चुनाव लड़े प्रत्याशी ज्यादा चर्चा में रहे। भाजपा की ओर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के तो, कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के चर्चे ज्यादा रहे। दोनों ही दलों के नेताओं ने ईनकी हर गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण किया। कांग्रेस ने मतदान समाप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र भारती को निलंबन का पत्र भी जारी कर दिया।

निश्चित रूप से उपचुनाव के परिणाम के बाद न केवल संगठन में बल्कि सरकार में भी हलचल बढ़ेगीं। एक और संगठन जहां अपनी कमियो का विश्लेषण करेगा वहीं सरकार भी अपनी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा पर मजबूत होगी और तय करेगी कि, आखिर चुक कहां हुई।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान बहुत मायना रखता है जिसमें वे स्वीकार कर रहे हैं कि, आखिर हार तो हार होती है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का यह भ्रम निश्चित रूप से टूटा होगा जिसमें वे आश्वस्त थे कि पार्टी के निशान पर वे किसी भी प्रत्याशी को विजयी बना सकते हैं। मतदाता, पार्टी के निशान के साथ ही उम्मीद्वार का भी बारीकी से विश्लेषण करता है।

जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो निश्चित रूप से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कद बढ़ेगा और पार्टी नए जोश के साथ आगामी चुनाव में उतरेगी।

भाजपा के लिए बिहार में भी इस चुनाव में अच्छी खबर नहीं आई जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं जीता सकी और जनसुराज के मंच तले पिछले चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली पार्टी के प्रशांत किशोर से करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और डबल इंजन वाली सरकार के नाम पर वोट मांगे गए लेकिन मतदाताओं ने विपक्ष का साथ देना उचित समझा, यहां की हार भी भाजपा के लिए चिंतन करने योग्य है। जबकि इस सीट पर भाजपा का पिछले 30 वर्षों से कब्जा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाली की गई सीट पर पूरे देश की निगाह थी।

तीन सांसदों ने एनडीए से दूरी बनाई, राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक से लगातार दूसरी बार तीन सांसदों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सांसदों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि, वे एनडीए के साथ अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर अलग रुख रखते हैं। मीडिया जानकारी के अनुसार संबंधित सांसद हाल ही में आयोजित गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे उनके और गठबंधन नेतृत्व के बीच मतभेदों की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकता है।

बताया जा रहा है कि, सांसदों की अनुपस्थिति कोई संयोग नहीं है, क्योंकि वे इससे पहले भी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक से दूरी बना चुके हैं। इस कारण उनके राजनीतिक भविष्य और संभावित रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर संबंधित सांसदों और गठबंधन नेतृत्व की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

वहीं, इस घटनाक्रम को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार यदि मतभेद बढ़ते हैं तो इसका असर गठबंधन की रणनीति और भविष्य की राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।

संसद की कार्रवाई और पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप तेज

नई दिल्ली।

संसद के मानसून सत्र के दौरान कार्यवाही बाधित होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सदन की कार्यवाही प्रभावित करने का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि वह जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहा है।

संसद परिसर और दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल छात्रों से जुड़े मामलों, कानून-व्यवस्था और अन्य विषयों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के कारण महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच बैठक भी हुई। बैठक में संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा को लेकर विचार-विमर्श किया गया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक गतिरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद के शेष सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने पर ही कार्रवाई सामान्य रूप से चल सकेगी।

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली।

संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को भी विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया।

विपक्ष ने छात्रों से जुड़े मामलों, विभिन्न जनहित मुद्दों तथा अन्य विषयों को लेकर सरकार से जवाब की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई दलों के सांसद एकजुट नजर आए और उन्होंने संबंधित मामलों पर चर्चा कराने की मांग उठाई।

संसद परिसर में हुए प्रदर्शन का असर सदन की कार्यवाही पर भी देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा।

वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य सुचारु रूप से चलाने की अपील की गई। संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए बातचीत के प्रयास भी किए गए।

बीमा नहीं तो ईंधन नहीं: बिना बीमा वाहनों पर सख्ती की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी कार्ययोजना

नई दिल्ली।

देश में बिना वैध बीमा के चल रहे वाहनों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को बीमा नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू करने की संभावना पर प्रायोगिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश में लगभग 30 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहनों में से करीब 16.54 करोड़ वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। यह कुल वाहनों का लगभग 56 प्रतिशत है। न्यायालय ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत तृतीय पक्ष बीमा अनिवार्य होने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पेट्रोलपंपों को ऐसी तकनीक से जोड़ा जाए, जिससे वाहन में वैध बीमा होने की पुष्टि के बाद ही पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जा सके। यदि वाहन का बीमा समाप्त हो चुका है तो बीमा नवीनीकरण तक ईंधन देने पर रोक लगाई जा सकती है। न्यायालय का मानना है कि इससे वाहन मालिक समय पर बीमा का नवीनीकरण कराने के लिए प्रेरित होंगे।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सड़कों और राजमार्गों पर लगे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों को बीमा डाटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ा जाए। इसके माध्यम से बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान कर स्वचालित रूप से चालान जारी किए जा सकेंगे। साथ ही यातायात पुलिस को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है, जिनसे मौके पर ही वाहन के बीमा की स्थिति की जांच की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि, बीमा का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। बिना बीमा वाले वाहनों के कारण पीड़ितों को मुआवजा प्राप्त करने में वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नए निजी चार पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य तृतीय पक्ष बीमा की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष तथा दो पहिया वाहनों के लिए पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि बीमा नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था अभी केवल प्रस्तावित चरण में है और इसे लागू करने से पहले तकनीकी, कानूनी तथा व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं से विस्तृत कार्ययोजना मांगी गई है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो देशभर में बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

जेन-जी का संदेश: मोदी सरकार बदलते भारत की आहट सुन रही है...?

जेन-जी और जेन अल्फा की बढ़ती अपेक्षाएँ सभी राजनीतिक दलों के लिए स्पष्ट संदेश, भविष्य की राजनीति केवल नारों से नहीं, बल्कि ठोस परिणामों, संवाद और विश्वास से होगी तय

माही की गूंज, झाबुआ। धर्मेंद्र पंचाल

लोकतंत्र में कई बार एक उपचुनाव पूरे राजनीतिक परिदृश्य का आईना बन जाता है। बिहार के बांकीपुर और मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम केवल दो सीटों की हार-जीत नहीं हैं, बल्कि वे देश की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत भी हैं। इन नतीजों ने यह संदेश दिया है कि भारतीय राजनीति अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ जातीय समीकरणों और परंपरागत वोट बैंक से अधिक महत्व रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलने लगा है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज मुंबई में आयोजित जेन-जी और जेन अल्फा सम्मेलन में नई पीढ़ी से संवाद करेंगे। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि, देश के प्रमुख सामाजिक और वैचारिक संगठन भी बदलती पीढ़ी की सोच, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समझने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। राजनीति हो या समाज, आने वाला समय युवाओं के साथ संवाद का होगा, केवल संदेश देने का नहीं।

हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और रोजगार के अवसरों को लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसकी बानगी भर है। यह असंतोष अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदान केंद्रों तक भी पहुँच रहा है। आज का युवा केवल वादों से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि ठोस परिणाम चाहता है।

बांकीपुर और दतिया के नतीजों को केवल चुनावी संयोग मानना उचित नहीं होगा। ये परिणाम संकेत देते हैं कि मतदाता विशेषकर युवा अब राजनीतिक दलों का मूल्यांकन परंपरागत निष्ठाओं से अधिक उनके प्रदर्शन, नीतियों और जवाबदेही के आधार पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें पहले से कहीं अधिक जागरूक, सूचना-संपन्न और मुखर बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीन लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। इसलिए केवल दो उपचुनावों के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी। लेकिन लोकतंत्र का इतिहास यह भी बताता है कि, छोटे चुनाव अक्सर बड़े राजनीतिक संकेत लेकर आते हैं। जनता पहले चेतावनी देती है, फिर निर्णय सुनाती है।

सबसे बड़ा परिवर्तन जेन-जी और उसके बाद उभर रही जेन अल्फा पीढ़ी है। यह पीढ़ी किसी स्थायी राजनीतिक विचारधारा या परंपरागत वोट बैंक से बंधी नहीं है। इसके लिए रोजगार, कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी अवसर, पारदर्शी शासन और बेहतर भविष्य सबसे बड़े मुद्दे हैं। यह पीढ़ी भावनात्मक नारों से अधिक ठोस परिणामों को महत्व देती है।

भाजपा के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि युवाओं की बढ़ती अपेक्षाएँ हैं। वहीं विपक्ष के सामने भी चुनौती कम नहीं है। केवल सरकार की आलोचना पर्याप्त नहीं होगी उसे एक विश्वसनीय, सकारात्मक और व्यवहारिक विकल्प भी प्रस्तुत करना होगा। नई पीढ़ी केवल विरोध नहीं, बल्कि समाधान चाहती है।

बांकीपुर और दतिया का संदेश स्पष्ट है लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक गढ़ स्थायी नहीं होता। जनता समय-समय पर सत्ता को यह याद दिलाती रहती है कि, अंतिम निर्णय मतदाता का होता है। यह संदेश केवल भाजपा के लिए नहीं, बल्कि देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए है।

मोदी सरकार के लिए यह समय संकट का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। यदि सरकार नई पीढ़ी की आकांक्षाओं, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और संवाद को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखती है, तो आज मिले ये राजनीतिक संकेत भविष्य की नई ऊर्जा बन सकते हैं। लेकिन यदि इन्हें सामान्य चुनावी उतार-चढ़ाव मानकर अनदेखा किया गया, तो यही छोटी-छोटी चेतावनियाँ आने वाले वर्षों में बड़े राजनीतिक बदलाव का आधार बन सकती हैं।

बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव तथा जेन-जी, जेन अल्फा पर बढ़ता राष्ट्रीय विमर्श इस बात का संकेत है कि भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकारें नहीं बदलते, वे समय की बदलती सोच का भी आईना होते हैं। आने वाले भारत की राजनीति उसी के हाथों में होगी, जो नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझेगा, उनसे संवाद करेगा और अपने वादों को परिणामों में बदलकर दिखाएगा।

एमपी की अजब पुलिसः डीजल चोरी का मामला सार्वजनिक

चोरी का डीजल लाने वाले को पुलिस ले गई चौकी पर और फिर भी पुलिस का रिकॉर्ड साफ सुथरा

माही की गूंज, झाबुआ/बामनिया।

अजब एमपी की झाबुआ पुलिस की कई कारस्तानियां व अनियमिताएं हमारे सामने है, जिसमें चोर को साहूकार और साहूकार को अपराधी बनाने में महारत हासिल कर चुकी है।

इसी कड़ी में झाबुआ जिले के बामनिया चौकी अंतर्गत सार्वजनिक चर्चा अनुसार सामने आ रहा है कि, दो-तीन दिन पूर्व चोरी का डीजल लेकर आ रहे दो युवकों को बामनिया पुलिस ने सूचना के आधार पर चार पहिया वाहन के साथ मय डीजल से भरी केनो के साथ पकड़ा गया। जिसका एक वीडियो भी माही की गूंज के सामने आया है। जिसमें बामनिया पुलिस का पुलिसकर्मी ने दो युवकों को पकड़ा है। वहीं सार्वजनिक चर्चा में यह भी सामने आ रहा है कि यह दो युवक खवासा चोकी क्षेत्र के है और उक्त मामला भाजपा के किसी मंडल स्तरीय एक नेता ने रफा-दफा करवा दिया गया।

हमारे संविधान अनुसार चोरी करने से बड़ा अपराध चोरी के माल को खरीदना होता है। ऐसे में अगर चोरी करने वाला पकड़े जाने पर किसी को माल बेचने की पुष्टि करता है और जांच में सही पाया जाता है तो चोरी का माल खरीदने वाला भी गिरफ्तार होता है। वही चोरी का माल खरीदने वाला चोरी करने वाले से पहले पकड़ा जाए तो उस चोरी करने वाले को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब डीजल चोरी के सार्वजनिक चर्चा के तथ्य को गहराई में जाकर माही की गूंज ने अंदर की बात को जाना तो सामने आया कि, झाबुआ-रतलाम सड़क निर्माण करने वाली हार्दिक कंट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी निर्माण में उपयोग मशीनों में से बड़ी मात्रा में केनो में डीजल चोरी कर सड़क निर्माण कार्य शुरू होने की दिनांक से ही लोगों को बेचा जा रहा है। हार्दिक कंट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी अपने मालिक को चूना लगाकर प्रतिदिन मशीनों के चलने के साथ वाहन में से अपने नियोजित टारगेट अनुसार प्रतिदिन जो डीजल चोरी किया जाता है उसे आसपास के लोगों को जो डीजल-पेट्रोल बेचते हैं या वाहन मालिक है से संपर्क किया और चोरी के उक्त डीजल को लेने अपनी आवश्यकता अनुसार पहुंच जाते हैं।

बामनिया पुलिस चोरी के डिजल के साथ इन 2 युवको को ले गई थी पुलिस चोकी पर।

उक्त डीजल हार्दिक कंट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग भाव से 50 से 70 रुपए लीटर में बेचा जाता है। उक्त डीजल चोरी का खेल रतलाम- झाबुआ सड़क निर्माण पर जहां तक मशीन निर्माण कार्य हेतु पहुंची है वहां तक उक्त डीजल चोरी का खेल हार्दिक कंट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। और जिले व क्षेत्र के एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ो से अधिक चोरी के डीजल खरीदने के मामले में आरोपित बन गए हैं। जब बामनिया पुलिस ने चोरी का डीजल खरीदने वाले को पकड़ने की जानकारी मिली तो सामने आया भामल के कोई भाजपाई के वरिष्ठ नेता हार्दिक कंट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों से थांदला-खवासा के मध्य जब सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ तब से अपनी मशीन व दुकान पर बेचने हेतु रेगुलर इन कर्मचारियों से चोरी का डीजल लाया जा रहा था। इसी प्रकार कई अन्य व्यक्ति भी है जो इस चोरी वाले डीजल को ले गए।

दो-तीन दिन पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता के पुत्र व जमाई बामनिया के लाड़की नदी स्थित अपना चार पहिया वाहन लेकर खाली केनो के साथ पहुंचे और लाड़की नदी स्थित हार्दिक कंट्रक्शन कंपनी के टेंपरेरी क्रोसर मशीन पर स्थित कर्मचारियों ने वाहनों में एवं मशीनों से डीजल चोरी किया वह करीब 200 लीटर चोरी का डीजल लेकर आ रहे थे। और सूचना पर बामनिया पुलिस ने चोरी का डीजल ला रहे दो आरोपित को पकड़ा और बामनिया चौकी पर ले गए। जहां चर्चानुसार मंडल के एक भाजपा नेता ने मामले को रफा दफा करवाया।

ऐसे में चोरी के डीजल ले जाने वाले चोरों को पुलिस चौकी तक ले गई और मामला रफा दफा के साथ पुलिस का रिकॉर्ड साफ- सुथरा ही साफ-सुथरा है।

पुलिस को मिली सूचना के बारे में जाना तो सामने आ रहा है कि, हार्दिक कंट्रक्शन कंपनी के किसी एक कर्मचारी को उक्त डीजल चोरी का हिस्सा नहीं मिला था जिसके चलते उसने उक्त जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी और यह मामला पुलिस तक पहुंचा। अगर पुलिस उक्त डीजल चोरी की इस पुरी तह तक जाती तो तय है पुलिस के पास एक बड़ा मामला दर्ज होता और बड़ी डीजल चोरी के खुलासे के साथ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ो डीजल चोरी करने वाले कर्मचारी व खरीदने वाले सामने आते।

खेर, अब तो भैंस गई पानी में...

27वीं बोल बम पैदल कावड़ यात्रा उज्जैन के लिए करेगी प्रस्थान

माही की गूंज ,पेटलावद।

सावन माह में भगवान शंकर की भक्ति में समूचा अंचल डूबा है। हर-हर महादेव की गूंज से शिवालय गूंज रहे है। वही इस पवित्र माह में कावड़ यात्राओं का दौर भी जारी हो गया। इसी क्रम में प्रतिवर्ष निकलने वाली 27 वी बोल बम पैदल कावड़ यात्रा इस बार भी उत्साह के साथ निकलेगी। कावड़ यात्रा अनंतखेड़ी-पेटलावद से 7 अगस्त शुक्रवार को बाबा महांकाल की नगरी उज्जैन के लिए प्रस्थान करेगी। इस बार कावड़ यात्रा का 27 वा वर्ष है। बोल बम कावड़ यात्रा के संचालन पंडित नरेंद्र नंदन दवे ने बताया कि यह यात्रा पेटलावद के गांव अनंतखेड़ी से जल भरकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लिए प्रस्थान करेगी और पांच वे दिन कावड़ यात्रियों द्वारा भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष निकलने वाली इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते है। यह पांच दिवसी पैदल कावड़ यात्रा 7 अगस्त शुक्रवार को अनंतखेड़ी से प्रस्थान करेगी जिसका पहला पड़ाव खाखरोड़ा स्थित माही मंदिर रहेगा। 8 अगस्त शनिवार को दूसरा पड़ाव बदनावर मे स्थित संजोग मैरिज गार्डन, में होगा, जहां धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाएंगे।

9 अगस्त रविवार तीसरा पड़ाव मोलाना के पाटीदार धर्मशाला मे रहेगा। 10 अगस्त सोमवार को चौथा पड़ाव ग्राम नलवा में होगा। 11 अगस्त मंगलवार को पांचवां एवं अंतिम पड़ाव उज्जैन आईमाता मंदिर रहेगा। इसके बाद सभी कांवड़ यात्री श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महादेव का विधि-विधान से जलाभिषेक करेंगे। यात्रा में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बच्चे बड़े बुजुर्ग शामिल होंगे। यात्रा का स्वागत नगर के अनेकों स्थान पर किया जाएगा।

बाजार में रोड के हाल बेहाल

माही की गूंज, काकनवानी।

काकनवानी मुख्य बाजार में घुसते ही बाईपास और मंडी मार्ग एवं बाजार में घुसते ही रोड के इतनी खस्ता हाल है कि, चार पहिया वाहन तो ठीक दो पहिया एवं पैदल यात्रियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। यहां बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं, इन गड्ढों में मिट्टी भरने से और भी कीचड़ का फैलाव हो रहा है लेकिन जिम्मेदार विभाग को इससे कोई लेना-देना नहीं है। इसी चौराहे पर बस स्टैंड होने से और भी ज्यादा दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है तो आम नागरिक परेशान हो रहा है। वही मच्छी एवं मटन मार्केट वाले भी गंदगी फैला रहे हैं जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत का होता है लेकिन पंच सरपंच और सचिव नहीं देख रहे हैं। आखिर इस गंदगी और गड्ढे,कीचड़ से कौन निजात दिलाएगा...?

बाबा नीलकंठेश्वर का मनमोहक श्रृंगार, दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु

माही की गूंज ,पेटलावद।

सावन माह के पावन अवसर पर नगर के प्रसिद्ध राजा भगवान नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर में भगवान महादेव का भव्य एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। श्रृंगार से पूर्व शहर के रमेश बैरागी ने भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का विशेष श्रृंगार किया। शिवलिंग को बाबा अमरनाथ के पवित्र बर्फानी बाबा के स्वरूप की सुंदर कलाकृति के रूप में सजाया गया। यह मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। श्रृंगार के दर्शन करने के लिए दिनभर और देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ती रही। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव के दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। रात्रि 8 बजे भगवान महादेव की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया।

महाआरती में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर दीपों की रोशनी, घंटियों की मधुर ध्वनि और शिव भजनों से गूंज उठा। महाआरती के पश्चात श्रद्धालुओं ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसादी ग्रहण की।

सावन के पवित्र माह में आयोजित इस धार्मिक आयोजन ने श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह का संचार किया। श्रावण मास के कार्यक्रमों सामाजिक मंडलो द्वारा सहयोग किया जा रहा है। भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के मनमोहक श्रृंगार और भव्य महाआरती ने पूरे नगर का वातावरण शिवमय बना दिया।

दतिया चुनाव की जीत पर कांग्रेस में जश्न , दो भागो में बटा कांग्रेस का खेमा

माही की गूंज , पेटलावद।

दतिया विधानसभा सीट पर हुए उप चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लेकर ढोल ,मिठाई , फटाखों के साथ सड़को पर उतर कर जीत का जश्न मनाया । पेटलावद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए पुराना नाका पर पहुंचे । लेकिन कुछ ही समय में कांग्रेस के बीच तकरार ओर गुटबाजी सामने आ गई । यहां कांग्रेस के दो गुटों द्वारा अलग अलग जश्न मनाया ,दोनों गुट पुराना नाका पर एक के बाद एक पहुंचे और दतिया विधानसभा सीट पर मिली जीत का जश्न मनाया।

मालू ओर वालसिंह गुट सक्रिय

विधानसभा टिकिट के होड़ में पेटलावद विधानसभा में दो गुट कार्य कर रहे है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष मालू अकमाल डामर के समर्थक तो दूसरा ग्रुप पूर्व विधायक वालसिंह मेड़ा का समर्थक है,दोनों ही नेताओं के समर्थकों ने अलग अलग जश्न मनाया । जिसको देख कर लोग भी आश्चर्य में पड़ गए ओर चर्चा में दोनों नेताओं के बीच चल रहे प्रभाव दिखाने की राजनीति पर चुटिया लेने लगे।

गैस एजेंसी के नाम पर ठगी थांदला निवासी पर कुकडेश्वर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

माही की गूंज, थांदला।

गैस एजेंसी में साझेदारी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित ठगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। कुकड़ेश्वर थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर झाबुआ जिले के थांदला निवासी सुजीत पिता ललित भाभर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) के तहत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, कुकड़ेश्वर निवासी पिंकी पति कन्हैयालाल पुरोहित ने शिकायत में आरोप लगाया कि गैस एजेंसी में साझेदारी और व्यवसाय में लाभ का भरोसा दिलाकर अलग-अलग समय पर करीब 55 लाख रुपये आरोपी के खातों में जमा कराए गए, लेकिन न तो साझेदारी दी गई और न ही राशि वापस लौटाई गई। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसी प्रकरण को लेकर हाल ही में कन्हैयालाल पुरोहित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर करीब 60 लाख रुपये की ठगी, दस्तावेजों के दुरुपयोग तथा झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की साजिश के आरोप लगाए थे। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आर्थिक लेन-देन, बैंक खातों, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है तथा विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फसल बीमा की राशि नहीं मिली, दो गांव के किसान पैदल पहुंच गए कलेक्टर के पास

किसान है, आतंकवादी नहीं जो बेरीकेट लगा कर रोका जा रहा है - जिलाध्यक्ष हामड

माही की गूंज , पेटलावद।

मंगलवार को पेटलावद क्षेत्र के किसान एक बार फिर उग्र होकर सड़को पर उतर गए, इस बार सरकार की फसल बीमा योजना को लेकर विकासखंड के बनी,जामली, टेमरियां, शामली,रूपगढ़ सहित कुछ गांव के किसानों को वर्षों से फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है,कई बार किसान इसको लेकर आंदोलन कर चुके है लेकिन स्थानीय अधिकारीयों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी ओर हर बार इस योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण भारी नुकसानी उठानी पड़ी, जबकि किसानों को बैंकों से मिलने वाले ऋण के साथ ही फसल बीमा की राशि काट ली जाती है। मंगलवार को क्षेत्र के किसान एक बार फिर उग्र हुए और इस बात स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगाने की बजाए जिला कलेक्टर कार्यालय लगभग सहाठ किलोमीटर पैदल ही चल पड़े, पैदल यात्रा कर झाबुआ कलेक्टर पहुंचे किसान अपने साथ राशन पानी की व्यवस्था भी कर के ले गए उद्देश्य था अगर उनकी समस्या का हल नहीं होता तब तक वो कलेक्टर कार्यालय के सामने से उठेंगे नहीं। सैकड़ों की संख्या में एक साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसानो को देख कर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए ओर किसानो को रोकने के लिए बेरीकेट लगा कर पुलिस बल लगा दिया लेकिन किसान बेरीकेट को हटा कर कलेक्टर कार्यालय के गेट पर जाकर बैठ गए। किसान नेता जीतेंद्र पाटीदार ने बताया कि फसल बीमा राशि के भुगतान से वंचित कई गांवों के किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हैं। लेकिन कई बार पेटलावद प्रशासन से मांग करने के बाद भी समस्या हल नहीं हुआ जिससे किसानों को लगातार आर्थिक नुकसानी उठानी पड़ रही है। किसानों के अधिकार के लिए कलेक्टर साहब के पास पहुंच कर हमारी मांग रखी है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेद्र हामड ने बताया कि सैटेलाइट के सर्वे के नाम पर किसानों को योजनाओं से वंचित किया जा रहा है और किसानों से बीमा राशि वसूल किसानो को दी जा रही हैं और सरकार फसल बीमा के नाम पर खुद की पीठ थपथपा रही है। किसान अपनी मांगो लेकर आते है तो प्रशासन आतंकवादियों तरह बेरीकेट लगा कर किसानों को रोक रही है।किसानों के भीड़ देख कर आखिर कलेक्टर भरसट को आना पड़ा ओर किसानो की मांग सुन कर उनको आश्वास्त किया। किसान नेता जीतेंद्र पाटीदार ने कहा, अगर फसल बीमा को लेकर प्रशासन ने जल्द ही समस्या का निराकरण नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

सारंगी में फर्जी पट्टे वितरण का एक और बड़ा मामला उजागर, जन सुनवाई में शिकायत

तहसील के लिए आवंटित भूमि पर ही दे डाले पट्टे, बदल गए एसडीएम के सुर कहा चार सौ बीसी का मामला पुलिस के पास जाओ

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

पेटलावद विकास खंड की ग्राम पंचायत सारंगी एक बार फिर से फर्जी पट्टे का एक ओर बड़ा खेल उजागर हुआ है। पिछली बार दो अलग-अलग शिकायत में ग्राम पंचायत ने एक शिकायत में समझौता कर मामला निपटा दिया था। तो दूसरी शिकायत में राजनीति प्रभाव का दुरुपयोग कर मामले को पूरी तरह से दबाया गया। उसके बाद अब एक ओर गंभीर मामला मंगलवार को जनसुनवाई में सामने आया जहां सारंगी से कुछ पट्टा धारकों ने मय पट्टे की छायाप्रति के साथ चौंकाने वाली बात ये है कि, जिस 1952 सर्वे नंबर पर वर्ष 2022 में पट्टे दिए गए वो भूमि वर्ष 2017-18 को हीं तहसील न्यायालय परिसर के लिए आवंटित की जा चुकी है।

फर्जी पट्टे दिए , पैसे लिए लेकिन कब्जा आज तक नहीं

पूर्व में 82 लाख वसूली के पट्टे देने की शिकायत ग्राम पंचायत सारंगी के विरुद्ध हुई थी जिसकी जांच रिपोर्ट आज तक शिकायतकर्ताओ को नहीं दी गई ओर हर बार यही बताया जाता है कि, जांच तहसील से कलेक्टर कार्यालय की ओर भेज दी गई है। मंगलवार को सारंगी से आए शिकायतकर्ताओं ने लिखित आवेदन देते हुए बताया कि, ग्राम पंचायत की सरपंच फुंदी बाई, सचिव हरिराम भूरिया ओर उप सरपंच रणजीत सिंह राठौर द्वारा राजस्व न्यायालय ओर माही प्रोजेक्ट की भूमि सर्वे नंबर 1952 को आबादी की भूमि बता कर अवैध पट्टा जारी किया ओर पट्टे के एवज में पांच-पांच लाख रुपए की राशि वसूली गई। लगभग 750 से 1000 स्क्वेअर फीट के पट्टे देने के चार साल बाद भी उक्त पट्टे की भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया। जबकि पट्टा देते समय भूमि आबादी की होकर ग्राम पंचायत में दर्ज बताई ओर मकान बनाने तक का प्रभोलन सरपंच ,सचिव ओर उप सरपंच द्वारा दिया गया।

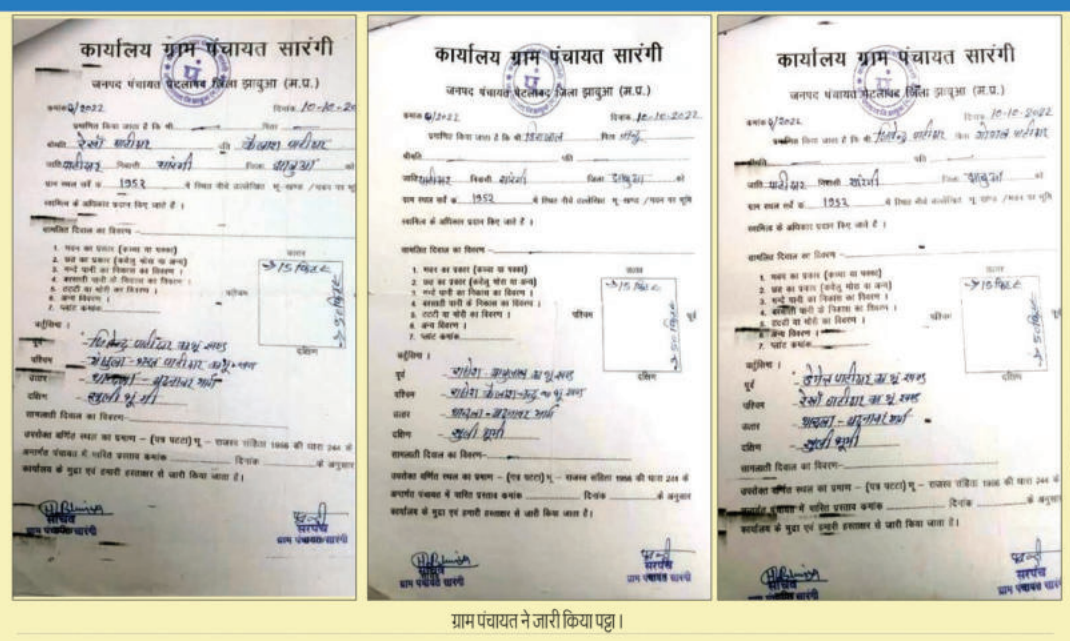
ग्राम पंचायत ने जारी किया पट्टा।

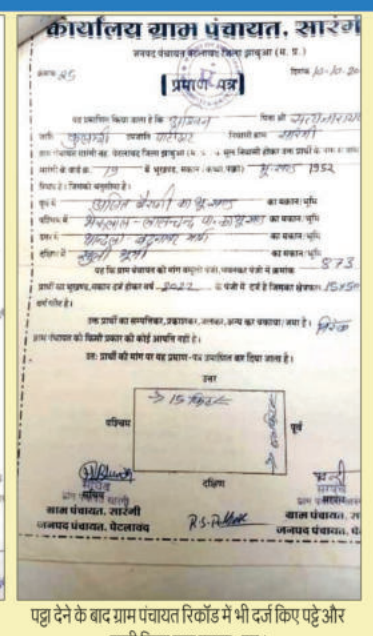
पट्टा देने के बाद ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में भी दर्ज किए पट्टे और जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

थमाई 500 की रशीद

शिकायतकर्ता ने बताया कि, पट्टे देने के नाम पर पांच-पांच लाख वसूले गए ओर रसीद मात्र 500 रुपए की दी गई। बाकी के पैसे का पूछने पर कहा गया कि, ये ऊपर तक बटेगें।

जन सुनवाई में फिर पहुंचे शिकायतकर्ता।

वर्तमान में ग्राम पंचायत सारंगी पर अवैध पट्टे देने के मामले में कार्रवाई की गई ओर राजस्व विभाग ने आवंटित पट्टे वाली भूमि राजस्व की बता कर अतिक्रमण माना ओर निर्माण हटा दिया गया। जब सर्वे नंबर 1952,1953 की जानकारी निकाली गई तो पट्टाधारकों को पता चला कि उक्त भूमि माही प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित ओर वर्तमान में राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन को आवंटित हो चुकी है, तब लोगों को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। शिकायकर्ताओं का आरोप है कि ग्राम पंचायत भली भांति जानती थी कि, उक्त भूमि राजस्व की है इसके बाद भी पट्टे दिए गए ओर पांच-पांच लाख की वसूली की गई।

ऑडियो, वीडियो भी उपलब्ध

शिकायत में बताया गया कि, पट्टे के नाम पर हुई लेन-देन के ऑडियो ओर वीडियो क्लिप भी सुरक्षित है जिसमें पट्टे देने वाले जिम्मेदारो की बातचीत स्पष्ट रूप से कैद है और उक्त बातचीत पट्टे के नाम पर ली गई राशि और पट्टे के स्थान पर कब्जा देने के लिए की गई है। शिकायत में ऑडियो, वीडियो के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने ओर इसकी जांच तक करवाने की बात कही गई। शिकायतकर्ताओं ने पट्टे के नाम से वसूली गई राशि वापस दिलवाए जाने के साथ कार्रवाई की मांग की है।

एसडीएम के बदले सुर, आदिवासियों को पट्टे क्यों नहीं

अजीब विडंबना है राजस्व विभाग मतलब जमीन मालिक की जमीन की खरीद-फरोख्त ग्राम पंचायत उसी की नाक के नीचे कर दी जाती है ओर राजस्व विभाग कार्रवाई करने की बजाए बेतुके तर्क देकर खुद को अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटता है।

जन सुनवाई में पहुंचे शिकायत कर्ताओं ने बताया कि, एसडीएम राजस्व तनुश्री मीणा ने पूर्व में की गई शिकायत के समय हमको कहा था कि, अगर शिकायत से बदले तो तुम लोगों पर कार्रवाई कर दूंगी, मतलब एसडीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए हमारे खिलाप कार्रवाई की बात की। लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती कर दी गई न कार्रवाई हुई न ही सही जांच। इस संबंध में जब नई शिकायत के साथ एसडीएम मीणा से शिकायतकर्ताओ ने पिछली शिकायत पर हुई कार्रवाई की बात पूछी तो मैडम के सुर बदल गए ओर एसडीएम ने मामले को 420 का मामला बताते हुए पुलिस और न्यायालय में जाने की बात कह दी। स्पष्ट है पूरे मामले में बड़ा झोल

भाजपा नेताओं ओर मंत्री के साथ सरपंच फुँदी बाई।

राजनीतिक रसुक का उपयोग किया गया है। राजस्व की भूमि पर बिना राजस्व की जानकारी के पट्टे काट कर वसूली करने वालो पर कार्रवाई के आदेश देने की बजाए एसडीएम पट्टे लेने वालों से पहले राजस्व से अनुमति लेने की बात कर रही है। जिससे साफ है कि, पूरे मामले को दबाने के लिए हर प्रकार के जरूरी प्रयास किए गए हैं जिसके दबाव ओर प्रभाव में अधिकारी साफ दिखाई दे रहे है। यहां बड़ा सवाल ये भी उठता है कि केवल सक्षम ओर ओबीसी वर्ग के लोगों को पट्टे दिए गए, बताया जा रहा है, टप्पा तहसील के पास खाली पड़ी भूमि जहां कचरा फेका जा रहा है उस भूमि पर भी पट्टे देकर बड़ी वसूली की गई है और इन पट्टा धारकों में बड़े ओर प्रभावी लोग शामिल है। जबकि गरीब, भूमि हीन आदिवासी लोगों को इस बेश कीमती भूमि पर पट्टे नहीं दिए गए, साफ है पट्टे के एवज में बड़ी रकम ली गई जो गरीब आदिवासी देने में सक्षम नहीं था।

शिकायत कर्ताओ को न्याय की उम्मीद

शिकायतकर्ताओ ने बताया कि, उन्हें न्याय की उम्मीद है ओर इसके लिए सिस्टम से आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कर रहे है। अगर न्याय स्थानीय स्तर से नहीं मिलता है तो आगे ओर भी जिम्मेदार एजेंसियां है वहां गुहार लगाएगें। ओर वहा भी न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय की शरण में भी जायेगे जहां सभी जिम्मेदारो को जवाब देना पड़ेगा।

ग्राम पंचायत सरपंच का एक मामला नहीं कई प्रकार अनियमिता ओर भ्रष्टाचार की सही जांच होने पर बडी ठगी उजागर हो सकते है।

सारंगी ग्राम पंचायत सरपंच फुँदी बाई मेड़ा, मंत्री निर्मला भूरिया के जन्मदिन पर स्वागत करती हुई, इस तस्वीर के बाद से फर्जी पट्टा कांड का मामला दबा हुआ माना जा रहा है।

थांदला के क्रिकेटर अर्पित भटेवरा को उनके शानदार घरेलू सीजन के लिए दिलीप ट्राफी टीम में जगह मिली

माही की गूंज, खवासा। हरिश भटेवरा

मेघालय के लिए एक ही रणजी ट्रॉफी सीजन में दो डबल सेंचुरी समेत करीब 900 रन बनाने के बाद, मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन ने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के अपने सपने की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला नगर में एक मिडिल-क्लास परिवार में जन्मे अर्पित के पिता उनके क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए बस कंडक्टर का काम करते थे।

वडोदरा से मेघालय का सफर

अर्पित ने कहा कि, इस साल की रणजी ट्रॉफी में उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस ने उनके दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन का रास्ता बनाया। वह पिछले सात-आठ सालों से फस्ट-क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे सफर में उनका साथ देने का क्रेडिट मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन को दिया। त्रिपुरा के साथ अपना डोमेस्टिक करियर शुरू करने के बाद, वह आखिरकार मेघालय चले गए, जहां उनके चाचा रहते हैं, और सालों की कड़ी मेहनत से खुद को जमाया।

वडोदरा ने क्रिकेट करियर की नींव रखी

हालांकि अर्पित असल में मध्य प्रदेश के थांदला के रहने वाले हैं, लेकिन 2010 में वे वडोदरा चले गए। जहाँ उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू किया। उनके पिता जो सूरत रूट पर बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे ने यह बदलाव मुमकिन बनाया।

अर्पित ने कहा, इस शहर ने मेरे करियर को बनाने में अहम भूमिका निभाई क्योंकि मुझे अपने शुरुआती सालों में भारत के पूर्व विकेटकीपर नयन मोंगिया और कोच मिलाप मेवाड़ा से गाइडेंस मिली।

पठान भाइयों ने उनका साथ दिया

अर्पित ने क्रेडिट दिया, ÷भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और यूसुफ पठान ने उनके करियर के कुछ सबसे मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। उन्होंने कोच सत्यजीत परब के गाइडेंस को भी माना, जो बड़ौदा से मेघालय आने के बाद भी उन्हें मेंटर करते रहे।

क्रिकेट का सपना जिंदा रखने के लिए छोटे-मोटे काम किए

अर्पित ने कहा, बड़ौदा में कम मौके मिलने के बावजूद मैंने कभी क्रिकेट छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। 2016 में मेघालय शिफ्ट होने के बाद, मुझे पैसे की तंगी झेलनी पड़ी, खासकर कोविड -19 महामारी के दौरान, जब घरेलू क्रिकेट रुक गया था। अपना गुजारा करने के लिए, मैंने कई छोटी-मोटी नौकरियां कीं और अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हुए स्पोर्ट्स से जुड़ा तथा बिजनेस भी शुरू किया।

माता-पिता ने कभी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा

अर्पित ने कहा, ÷मेरे माता-पिता,'' खासकर मेरी माँ के पक्के सपोर्ट ने मुझे अपने सपने का पीछा करते रहने में मदद की। कई सालों तक बीसीसीएल टूर्नामेंट में मौके नहीं मिलने के बावजूद, मेरे माता-पिता ने मुझ पर कभी पक्की नौकरी ढूंढने का दबाव नहीं डाला जो नोकरी करता उसे ही करने दिया और मुझे कड़ी मेहनत करते रहने के लिए हिम्मत दी।

आईपीएल और टीम इंडिया का सपना

अब अपनी घरेलू सफलता को आगे बढ़ाने का पक्का इरादा रखने वाले अर्पित को उम्मीद है कि, वह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रणजी ट्रॉफी और दूसरे टूर्नामेंट में अपना लगातार अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगें। उनका मानना है कि, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने से आखिरकार भारतीय टीम में उनके लिए जगह बन सकती है, जो उनका आखिरी सपना है।

पिता का त्याग सबसे बड़ी प्रेरणा है

एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले अर्पित ने कहा, बस कंडक्टर के तौर पर मेरे पिता की सालों की सर्विस ने मुझे सफल होने के लिए प्रेरित किया। मैं, इंडियन क्रिकेट में खुद को स्थापित करके और अपने परिवार का भविष्य सुधारकर अपने माता-पिता के त्याग का बदला चुकाना चाहता हूं।

पांड्याभाई लगातार उनकी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं

अर्पित ने बताया कि, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, इरफान पठान और यूसुफ पठान के साथ उनका करीबी रिश्ता है, इन सभी ने उनके पूरे करियर में उनका साथ दिया है। रणजी ट्रॉफी में डबल सेंचुरी बनाने के बाद, क्रुणाल पांड्या ने उन्हें एक बैट गिफ्ट किया, जबकि इरफान और यूसुफ दोनों ने दलीप ट्रॉफी में चुने जाने पर उन्हें पर्सनली बधाई दी।

परफॉर्मेंस ही उनका एकमात्र फोकस है

आईपीएल में मौके के बारे में पूछे जाने पर अर्पित ने कहा कि, अभी तक किसी फ्रेंचाइसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन उनका मानना है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने से उन्हें आखिरकार जगह मिल जाएगी। उन्होंने कहा, मोहम्मद सिराज, चेतन सकारिया और मयंक यादव जैसे खिलाड़ियों ने टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए आईपीएल को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया, और उम्मीद है कि घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करके वे भी इसी रास्ते पर चलेगें।

चोरों का आतंक, तीन घरों के ताले टूटे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

माही की गूंज, थांदला।

नगर में बीती रात एक सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात में हथियारों से लेस अज्ञात बदमाश 2.60 लाख नकद सहित सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर भाग खड़े हुए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसी टीवी कैमरों में कैद होने के बावजूद बदमाश अभी पकड़े नहीं जा सके हैं।

सोमवार रात्री में हुए घटनाक्रम में मिली जानकारी अनुसार जिले के थान्दला नगर के वार्ड क्रमांक 3 स्थित गवली मोहल्ले में सोमवार एवं मंगलवार की दरमियानी रात में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्मित कर दिया है। छह बदमाशों ने किराए के मकान में रह रहे इरशाद कुरैशी नामक व्यक्ति के सूने घर का ताला तोड़कर 2.60 लाख नकद,सोने की चेन और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला हार सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, बावजूद उसके बदमाश अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चोरी की घटना के दोरान इरशाद कुरैशी अपने परिजन की बीमारी के चलते घटना की रात अपने घर पर नहीं थे और बदमाशों ने इसी बात का लाभ उठा कर मकान का ताला तोड़ा और घटना को अंजाम दिया।

थाना प्रभारी थांदला अशोक कनेश ने घटना की जानकारी चाहे जाने पर मंगलवार को कहा कि, नगर में तीन जगहों पर बदमाशों द्वारा ताले तोड़े गए थे, और एक जगह वारदात को अंजाम देने में सफल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थांदला पुलिस मौके पर पहुंची, और कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी गई। सीसी फुटेज में छह संदिग्ध बदमाश हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

संपादकीय

जन्म-मृत्यु पंजीकरण

यह जरूरी है कि देश में जन्म व मृत्यु से जुड़े आंकड़े प्रामाणिक हों और समय रहते दर्ज कर लिए जाएं। इससे जनसंख्या गणना, मतदाता की विश्वसनीयता और अंततरू विकास योजनाओं के लिये विश्वसनीय आंकड़े जुटा पाना संभव होता है। वहीं दूसरी ओर अवैध घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों की पहचान भी संभव हो पाती है। जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसी आलोक में संसद द्वारा हाल ही में 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण(संशोधन) विधेयक' को पारित करना, देश की नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल, यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि जन्म व मृत्यु का पंजीकरण समय रहते कर लिया जाए। यह कानून देर से होने वाले पंजीकरण के लिए सख्त नियम लागू करता है। नये संशोधन के तहत, जन्म व मृत्यु के दो साल बाद रिपोर्ट किए गए मामलों में मौजूदा कार्यकारी मंजूरी की जगह अब प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। निस्संदेह, फर्जी पंजीकरण को रोकने की दिशा में सरकार का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन यह संशोधन लोगों की पहुंच और समावेशिता के बाबत कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। निस्संदेह, आज देश ने सिविल रजिस्ट्रेशन यानी जन्म-मृत्यु पंजीकरण के मामलों में बहुत अच्छी प्रगति की है। आज देश में 99 फीसदी से अधिक जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखा जाता है। दरअसल, देश में बड़ी चुनौती सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि जन्म व मृत्यु होने पर 21 दिन के भीतर सूचना दर्ज कर ली जाए। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि प्रक्रियागत बाधाएं बढ़ाने की बजाय, समय पर रिपोर्टिंग करने को सहज व सरल बनाया जाए। लोगों को इस बाबत जागरूक करने की भी जरूरत है। साथ ही मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने से अधिक नीतिगत मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार का दावा है कि न्यायिक जांच से पंजीकरण में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगायी जा सकेगी।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि वर्ष 2023 संशोधनों के तहत कई सरकारी सेवाओं के लिये जन्म प्रमाण पत्र पहचान का मुख्य दस्तावेज बन गया है। हालांकि, इस बाबत दो साल की समय-सीमा चुनने के पीछे की वजह को तार्किक आधार पर नहीं बताया गया है। वहीं कई ऐसे वाजिब कारण हैं जिसके चलते पंजीकरण देर से होता है। उदाहरण के लिये लें तो दूरदराज के इलाकों में जन्म, पलायन और जागरूकता की कमी के कारण भी जन्म-मृत्यु के पंजीकरण में विलंब होता है। लेकिन अब नये कानून से प्रभावित परिवारों के लिये खर्च और देरी, दोनों ही बढ़ सकते हैं। यह विडंबना ही है कि यह बिल संसद के दोनों सदनों में जारी लगातार हंगामे के बीच पास हुआ। जिसकी वजह से इस महत्वपूर्ण बिल पर कोई सार्थक बहस नहीं हो सकी। वास्तव में होना तो यह चाहिए था कि हर नागरिक की कानूनी पहचान को प्रभावित करने वाले कानून की गहनता से पड़ताल की जाती। जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। निस्संदेह, कुशल प्रशासन में कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने और चुनावी ईमानदारी के लिये एक मजबूत व पारदर्शी नागरिक पंजीकरण प्रणाली अपरिहार्य ही है। वास्तव में इस संशोधन की प्रभावशीलता को सिर्फ धोखाधड़ी रोकने की क्षमता से नहीं देखा जाना चाहिए। सावधानी इस बात को लेकर भी की जानी चाहिए कि कोई भी वास्तविक नागरिक कानूनी पहचान से वंचित न रह जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सुरक्षा उपाय नागरिकों की पहुंच में बाधा नहीं बनने चाहिए। सही मायने में अच्छी गवर्नेंस, प्रशासनिक ईमानदारी और लोगों के अधिकारों, दोनों को ही सुरक्षित रखने में है। यह जरूरी है कि लोग समय पर जन्म व मृत्यु की सूचना का पंजीकरण कराएं, लेकिन इसे दर्ज करने की प्रक्रिया सहज-सरल होनी चाहिए। जिसके लिए लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। साथ ही अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब पर सख्ती करने के बजाय सुधारात्मक प्रयासों को तरजीह दी जानी चाहिए।

जंतर-मंतर पर सुरक्षा तैयारी में चूक के सबक

मैंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हो रही कुछ गतिविधियों को देखा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बहुत बड़ी थी और उसकी तुलना में कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस बल नाकाफी लग रहे थे। एक विशाल और अराजक भीड़ और कम संख्या में पुलिसवाले होना स्थिति बेकाबू बनने में आवश्यक घटक होते हैं। जब मैं इस बारे में विचार करता हूं, तो यह स्पष्ट है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बुलावे पर लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाने में भारी गलती हुई, नतीजन सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया भी पर्याप्त नहीं थी।

विगत में पीछे मुड़कर देखें तो चर्चा में 'कॉकरोच' शब्द की आमद के बाद स्थिति तेजी से बदली। बोस्टन से आए एक व्यक्ति ने संसद तक मार्च का आह्वान कर नई दिल्ली में अपने किस्म की 'टी पार्टी' (चाय पार्टी) बनाने की कोशिश की। किसी सभा या विरोध-प्रदर्शन की इजाजत देने या न देने का फैसला मात्र पुलिस का न होकर शहर अथवा राज्य के नागरिक प्रशासन का भी होता है।

पुलिस बल राजसत्ता का एक औजार है और उसका पेशेवर व्यवहार तय कर सकता है कि स्थिति बिगड़ेगी या काबू में रहेगी। मौजूदा मामले में, अधिकारियों ने तैयारी और योजना बनाने का वक्त गंवा दिया क्योंकि उन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया के पैमाने का सही अंदाजा नहीं लगाया व स्थिति एक असमान टकराव में बदल गई।

आमतौर पर, जब भी ऐसे किसी मार्च की घोषणा होती है, तो जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी अतिरिक्त सक्रिय हो जाती है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक तथा खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मिलकर बैठक करते हैं, खतरे के स्तर का आकलन किया जाता है व उससे निबटने के लिए आपातकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं। बलों की जरूरत का आकलन किया जाता है और लाठीचार्ज दस्ता, आंसू गैस, हथियारबंद टुकड़ियों आदि की उपलब्धता का अनुमान लगाया जाता है। अगर और ज्यादा कर्मियों एवं सामग्री की जरूरत दिखे, तो जरूरी मांग की जाती है।

सूचीबद्ध किए गए इंतजामों की देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और सिर्फ उन्हीं को चुना जाता है जिनका अनुभव विगत में ऐसी स्थितियों को संभालने का साबित हो चुका हो। इसके साथ ही, कार्यकारी मजिस्ट्रेट नामित किए जाते हैं और उन्हें पुलिस अधिकारियों से संलग्न कर दिया जाता है। इलाके को सेक्टरों में बांटा जाता है और इन अधिकारियों को काम करने के निर्दिष्ट इलाके सौंप दिए जाते हैं। सभी इंतजामों की कुल मिलाकर निगरानी के लिए एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऊपर बताए गए सभी उपायों का ध्यान रखा गया है। वह सभी विभागों के अधिकारियों को उद्देश्य के बारे में निर्देश देता है और आगे वे अपनी-अपनी जिम्मेदारी वाले इलाकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हैं।

स्थिति क्या है यह बताना और समझाना सबसे जरूरी है ताकि आखिरी व्यक्ति तक को खतरे और उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, इसकी समझ बन जाए। बल का इस्तेमाल इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि वांछित अधिकतम परिणाम पाने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग करना पड़े। अधिकारियों और जवानों को यह याद रखना चाहिए कि ये हमारे ही भाई-बंधु हैं और हमें उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा परिणाम पाने के लिए कम-से-कम बल का इस्तेमाल किया जाए। पूरे अभियान की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए।

आंसू गैस दस्ते को एक रणनीतिक जगह पर एक राजपत्रित अधिकारीकी देखरेख में अलग से तैनात किया जाना चाहिए और वह केवल उनके आदेश पर ही काम करेगा। इसी प्रकार, हथियारबंद दस्ता भी एक राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित जगह पर उपलब्ध रहे और वह केवल उनके आदेश पर ही कार्रवाई करेगा। आंसू गैस के गोले और अन्य हथियार सामान्य बलों को नहीं दिए जाएंय नियम के अनुसार उनके पास केवल लाठियां होनी चाहिए।

इंतजाम का एक और बहुत जरूरी हिस्सा कंट्रोल रूम है, जिसे ऑपरेशन वाली जगह के पास स्थापित किया जाना चाहिए और वहां चौबीसों घंटे वरिष्ठ अफसर मौजूद रहें। कंट्रोल रूम और सेक्टर इंचार्ज अफसरों के पास नवीनतम संचार उपकरण होने चाहिए और संवाद का एक असरदार चौनल बनाया जाना चाहिए।

सीनियर अफसरों को इस कंट्रोल रूम में मौजूद होना चाहिए- पुलिस और एग्जिक्यूटिव अफसर ,दोनों केवल अपने दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रहें। एक बार जब इंतजाम पूरे हो जाएं, अफसरों और जवानों को स्थिति संबंधी निर्देश और जानकारी दी जाए और पूर्वाभ्यास किया जाए, वरिष्ठ अधिकारी भीड़ की संख्या और इरादों के बारे में ताजा जानकारी के लिए खुफिया एंजेसियों के संपर्क में रहें। अगर हो सके, तो वरिष्ठ सिविल और पुलिस अफसरों को आयोजकों से मिलना चाहिए और वे उन्हें शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से विरोध करने की अहमियत समझाएं। यह कोशिश अलग-अलग स्तरों पर की जानी चाहिए, और आमतौर पर इसके अच्छे नतीजे मिलते हैं। उस दिन, मैंने टीवी पर एक अकेले पुलिसवाले को स्पष्ट तौर पर दिशा अथवा उद्देश्य की पूरी तरह समझ के बिना आंसू गैस के गोले छोड़ते देखा। इसी तरह, प्रदर्शनकारियों के समूहों का पीछा करते हुए पुलिसवाले तरह-तरह की लाठियों और डंडों से लैस होकर दौड़ रहे थे। वे एक या दो प्रदर्शनकारियों को पकड़ लेते और उनकी पिटाई करने लगते।

वर्दीधारी फोर्स की कार्रवाई एक व्यवस्थित प्रयास होना चाहिएय लाठीचार्ज जवानों के एक दस्ते द्वारा होना चाहिए और इस प्रकार कि भीड़ को तितर-बितर करने में असरदार हो सके। बिना सोचे-समझे, अव्यवस्थित तरीके से लाठियां भांजने से कोई सकरात्मक नतीजा नहीं मिलता- इससे केवल निर्मम बल प्रयोग के आरोप लगते हैं या सिर में चोट जैसे परिणाम रहते हैं। बल का इस्ते माल निगरानी में

गुरबचन जगत

किया जाना चाहिए कृ नियंत्रित, नपा-तुला और भीड़ को तितर-बितर करने के मकसद को पूरा करने योग्य पर्याप्त। उद्देश्य किसी भी कीमत पर 'दुश्मन' को हराना नहीं है, क्योंकि इससे और ज्यादा प्रतिरोध बनेगा, लोग और अधिक भड़क जाएंगे। एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद, जवानों और सामान को व्यवस्थित तरीके से वापस बुलाया जाए। हर व्यक्ति, लाठी, आंसू गैस के गोले और गोली का हिसाब रखा जाए। घायल अफसरों और प्रदर्शनकारियों की देखभाल करें, और जरूरत पड़ने पर उन्हें चिन्हित अस्पतालों में ले जाया जाए।

यह विषय बहुत बड़ा है, और मैंने योजना और पहले से तयशुदा प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करने की अहमियत को संक्षेप में बताने की कोशिश की है। दिल्ली प्रशासन के लिए यह अच्छा होगा कि वह इस बात की अंदरूनी और गहराई से जांच करे कि क्या हुआ था और आईंदा इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। आज समस्या यह है कि निर्देश प्रक्रिया में बताए तरीकों में ज्यादातर को नजरअंदाज कर दिया जाता है या उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पुराने समय में अधिकारियों एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा नियमित प्रशिक्षण और निरीक्षण का महत्व काफी था। सच तो यह है कि आज हमारे पुलिस बलों और असल में संपूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था के आचरण में निहित संस्कृति और कामकाज के तरीके में बहुत कुछ भुला दिया गया है।

बांकीपुर की जीत बदलेगी सियासत की दिशा

एक राज्य का उपचुनाव का परिणाम किस तरह पूरे देश भर में अपनी धमक दिखा सकता है, इसे बिहार बांकीपुर चुनाव के नतीजे आने के बाद महसूस किया जा सकता है। इस एक सीट ने देश की सियासत के कई संदेश एक साथ दे दिए हैं। बांकीपुर की वह सीट, जिसमें कई कारणों से बीजेपी के लिए चुनाव एक औपचारिक-सा माना जा रहा था वहां उसके प्रत्याशी का लगभग 19 हजार वोटों से पीछे रह जाना सबको चौंकाया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन का गढ़ मानी गई इस सीट पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। 1995 से बीजेपी यहां कोई चुनाव नहीं हारी थी। इस सीट को नवीन परिवार की सीट कहा जाता रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी विधानसभा चुनाव में 238 में 233 सीटों पर जमानत जब्त कराकर हाशिए पर थी। ऐसे में उपचुनाव का यह नतीजा जहां बीजेपी को आत्ममंथन करने के लिए विवश करता है वहीं विपक्ष की बड़ी पार्टियों को भी यह अवसर नहीं देता कि इस जीत पर उल्लास मना सकें। खासकर इस सीट पर जो आरजेडी जमानत नहीं बचा सकी उसके लिए भी बिहार की सीमाओं में स्पष्ट संदेश है।

वर्ष 2024 मे लोकसभा में अयोध्या की सीट हारने के बाद बीजेपी के लिए बांकीपुर विधानसभा की सीट हारना दूसरा सदमा है। इस चुनाव ने बताया है कि चुनावी रणनीति ठीक हो, मतदाताओं के साथ संवाद हो और लागलपेट के बजाय सहजता से अपने मुद्दों को रखा जाए तो वोट बरस सकते हैं। कुछ महीनों में ही अगर मतदाताओं की सोच में इतना फर्क आया है तो फिर बीजेपी को आकलन करना होगा कि इस अवधि में ऐसे कौन से घटनाक्रम हुए जिनसे मतदाता का मन बिल्कुल बदल गया। बीजेपी ने नामांकन खत्म होने से पहले एकाएक अपनी पार्टी का उम्मीदवार बदला। इससे साथ ही भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सवर्णों में निराशा फैली। कहीं न कहीं ऐसे अवसर पर दिल्ली में छात्रों के

आक्रोश से भी किसी हद तक माहौल बदला। बीजेपी की कार्यशैली के साथ साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयानों ने भी मतदाताओं को नाराज किया।

बीजेपी के प्रभाव वाले वोट जनसुराज पार्टी को मिले बिना इस तरह की बड़ी जीत हासिल करना संभव नहीं था। प्रशांत किशोर को बीजेपी के मत भी मिले और आरजेडी के भी। साथ ही इस चुनाव ने इस धारणा को भी और सबल बना दिया कि राष्ट्रीय पार्टियों के तौर-तरीके और शैली में जनता कहीं किसी बदलाव की अपेक्षा कर रही है। फिर वह चाहे तमिलनाडु में विजय थलपति को सत्ता थमाना हो या फिर बांकीपुर की सीट उन प्रशांत किशोर को सौंपनी हो, जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे।

ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट पर जीत कर बड़े नायक बन गए हों। लेकिन उनकी जीत ने सियासत की कई संभावनाओं को सामने रख दिया है। इसका संदेश बिहार सहित पूरे देश के लिए है। प्रशांत किशोर ने राजनीति के मिजाज को बखूबी समझा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से न तो वह विचलित हुए न हताश हुए। उन्होंने कोई अनर्गल बयान नहीं दिया। एसआईआर पर भी वह ज्यादा नहीं बोले। वह जिस तरह बांकीपुर के मतदाताओं के समक्ष गए उसकी थाह मतदाताओं ने ली। बीजेपी या आरजेडी से हताश हो रहे मतदाता ने प्रशांत किशोर को सबसे बेहतर विकल्प माना।

देश में कुछ उपचुनाव ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को बदला। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी। लेकिन दक्षिण भारत में उसे आधार मिला था। यहीं से कर्नाटक की लोकसभा एक सीट चिकमगलूर डीबी चंद्रगौड़ा ने इस्तीफा देकर खाली की थी। इंदिरा गांधी ने यहीं से उपचुनाव लड़ा था। यह उपचुनाव के लिए जनता पार्टी ने जनता दल के कद्दावर नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आपसी मतभेद में जूझ रही जनता पार्टी के लिए चिकमगलूर का परिणाम आगे का संकेत लेकर आया था।

उपचुनाव की बात करें तो पौड़ी संसदीय क्षेत्र में 1981 का चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प रोमांचक चुनाव कहा जा सकता है। यह चुनाव सीधे-सीधे कद्दावर नेता हेमवती नंदन और पीएम इंदिरा गांधी के बीच प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया था। हालांकि, चुनाव लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता एचएन बहुगुणा और कांग्रेस के चंद्र मोहन सिंह नेगी के बीच था। एचएन बहुगुणा जनता पार्टी के टूटने पर 1980 में फिर से कांग्रेस में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में पौड़ी सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन संजय गांधी से उनका तालमेल नहीं बैठा। यह उनका नैतिक आधार था कि जिस पार्टी को छोड़ा है उसके टिकट पर सांसद बने रहने का औचित्य नहीं है। उन्हें दोबारा जनादेश लेना चाहिए। यही बात कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को खटकी थी। कांग्रेस ने पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रचार में उतारा था।

वेद विशाल उनियाल

तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने दो सभाएं की थीं। 14 जून, 1981 को इस सीट पर ऐतिहासिक चुनाव हुआ था। लेकिन तब कुछ गड़बड़ियों की शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्याम लाल शकधर ने चुनाव रद्द कर दिया था। दोबारा चुनाव होने पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने 42 हजार की लीड लेकर चुनाव जीता था। इस चुनाव का महत्व यह भी था कि देश में चुनाव सुधार और पारदर्शी मतदान के लिए एक नई बहस ने जन्म लिया था।

गहन अंतरिक्ष में विचरता धरती का अनोखा सैलानी

नासा के वॉयेजर 1 यान का गहन अंतरिक्ष में लंबा सफर आज भी जारी है और वह जल्द ही एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। छोटी कार के आकार का यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का पहला ऐसा यान है, जो अंतर-नक्षत्रीय अंतरिक्ष (दो तारों के बीच का अंतरिक्ष) में पहुंचने में कामयाब हुआ है। लगभग 50 सालों से यह यान पृथ्वी से 61,100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूर जा रहा है। हैरानी की बात है कि इतने वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी यह अभी तक पृथ्वी से 1 प्रकाश दिवस (लाइट डे) की दूरी तक नहीं पहुंच पाया है। अब नासा के वैज्ञानिकों ने उस सटीक समय का पता लगा लिया है, जब ऐसा होगा और हम उससे बस कुछ ही महीने दूर हैं। यह यान 18 नवंबर, 2026 को दोपहर 3रू46 बजे अपने गृह ग्रह से 25.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा।

प्रकाश दिवस दरअसल उस दूरी को कहते हैं, जिसे प्रकाश एक दिन में तय करता है। अंतरिक्ष में दूरियां बताने के लिए वैज्ञानिक प्रकाश दिवस के अलावा प्रकाश वर्ष का भी बार-बार उल्लेख करते हैं। प्रकाश वर्ष दरअसल दूरी की एक इकाई है, जो यह मापती है कि प्रकाश की किरण एक वर्ष में अंतरिक्ष में कितनी दूरी तय करती है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में प्रकाश लगभग 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। चूंकि प्रकाश को अंतरिक्ष में यात्रा करने में समय लगता है, इसलिए दूर स्थित किसी वस्तु को देखने का अर्थ है कि आप उसे वैसा देख रहे हैं, जैसा वह अतीत में दिखता था। उदाहरण के लिए, हमारा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटौरी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगते हैं।

वॉयेजर 1 को एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने में 49 साल से ज्यादा का समय लगेगा। वॉयेजर 1 और उसका जुड़वां यान वॉयेजर 2 ऐसे अंतरिक्ष यान हैं, जो हेलियोस्फीयर (सूरज से निकलने वाले कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का सुरक्षा कवच) के बाहर काम कर रहे हैं। वॉयेजर 1 का असली मिशन बृहस्पति और शनि के पास से गुजरना था। ये लक्ष्य उसने क्रमशः 1979 और 1980 में पूरे कर लिए। इसके बाद वह गहन अंतरिक्ष में आगे बढ़ता ही गया।

इस सफर के दौरान वॉयेजर 1 और 2 ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरते हुए तस्वीरें भेजी हैं। दोनों यानों ने चारों विशाल ग्रहों का अध्ययन किया। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर पृथ्वी से परे पहले सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की। दोनों यानों ने मिलकर 22 नए चंद्रमाओं की खोज की। इनमें बृहस्पति के 3, शनि के 3, यूरेनस के 10 और नेपच्यून के 6 चंद्रमा शामिल हैं। दोनों ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर सतह के नीचे तरल महासागर के पहले संकेतों का पता लगाया। उन्होंने बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून की जटिल वलय प्रणालियों (रिंग सिस्टम) की तस्वीरें भी लीं।

वॉयेजर 1 ने 25 अगस्त, 2012 को अंतर-नक्षत्रीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया, जिसके बाद वॉयेजर 2 ने 5 नवंबर, 2018 को अंतर-नक्षत्रीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया। दोनों यान सबसे दूर स्थित मानव-निर्मित वस्तुएं हैं, जो दशकों पुरानी तकनीक के माध्यम से संचार करती हैं।

वॉयेजर मिशन के इतना आगे बढ़ने के बावजूद प्लूटोनियम से चलने वाले इस अंतरिक्ष यान की ऊर्जा धीरे-धीरे खत्म हो रही है। इसे थोड़े और समय तक चालू रखने के लिए नासा पिछले एक साल से इसके उपकरणों को एक-एक करके बंद कर रहा है। अब उसके पास सिर्फ दो उपकरण बचे हैं। ये हैं मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा वेव सबसिस्टम, जो अभी भी तारों के बीच के अंतरिक्ष की हल्की विद्युत-चुंबकीय धड़कन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नासा का अनुमान है कि यह अंतरिक्ष यान 2030 के दशक की शुरुआत तक पृथ्वी के साथ संपर्क बनाए रखेगा। उम्मीद है कि तब तक इसकी पावर सप्लाई किसी भी चीज को चलाने के लिए जरूरी स्तर से नीचे नहीं जाएगी।

लेकिन बंद होने का मतलब इसके मिशन का अंत नहीं होगा। वॉयेजर 1 और 2 दोनों में सोने की परत चढ़ी तांबे की डिस्क लगी हैं, जिन्हें 'गोल्डन रिकॉर्ड' कहा जाता है, जिन पर पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति से जुड़ी जानकारी उकेरी गई है। वॉयेजर की डिस्क पर 50 से अधिक भाषाओं में अभिवादन के अलावा धरती की आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं। डिस्क पर रिकॉर्ड की गई भाषाओं में हिंदी सहित प्रमुख भारतीय भाषाएं शामिल हैं। केसरबाई केरकर द्वारा गाई गई एक प्रसिद्ध शास्त्रीय ठुमरी, 'जात कहां हो', को भी डिस्क में शामिल किया गया है।

इसमें एक पल्सर नक्शा है, जो ब्रह्मांड में पृथ्वी की लोकेशन दिखाता है। उन्नत पारलौकिक सभ्यताएं इस नक्शे की मदद से पृथ्वी को खोज सकती हैं। गोल्डन रिकॉर्ड में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक शुरुआती संदेश भी शामिल है। जब वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ था, तब वे ही राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने संदेश में कहा था, हम यह संदेश ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। मुमकिन है कि यह हमारे भविष्य में एक अरब साल तक सुरक्षित रहे। तब तक हमारी सभ्यता पूरी तरह बदल चुकी होगी और धरती की सतह भी शायद बहुत बदल गई होगी। मिल्की वे आकाशगंगा में मौजूद 200 अरब तारों में से कुछ या शायद कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं, जहां जीवन हो। वहां अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सभ्यताएं हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई सभ्यता वॉयेजर को ढूंढ़ लेती है और इसमें रिकॉर्ड की गई चीजों को समझ पाती है, तो उसके लिए हमारा संदेश यह हैकृ'यह एक छोटी-सी दूर की दुनिया की तरफ से तोहफा है। यह हमारी आवाजों, हमारे विज्ञान, हमारी तस्वीरों, हमारे संगीत, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की एक निशानी है। हम अपने समय में टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आपके समय तक पहुंच सकें। हमें उम्मीद है कि एक दिन, अपनी समस्याओं को सुलझाकर, हम आकाशगंगा की सभ्यताओं के समुदाय का हिस्सा बन पाएंगे। यह रिकॉर्ड हमारी उम्मीद, हमारे संकल्प और इस विशाल एवं अद्भुत ब्रह्मांड के प्रति हमारी सद्भावना को दर्शाता है।'

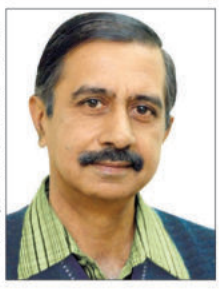

मुकुल व्यास

दुल्हनों का सौदा: दलालों पर भरोसा करके शादी के कुछ ही दिनों बाद ही टूट रहे रिश्ते

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में बिहार की 23 वर्षीय नवविवाहिता संध्या कुमारी की संदिग्ध मौत ने दलालों के माध्यम से कराए जा रहे अंतरराज्यीय विवाहों के नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में विवाह के लिए 2.60 लाख रुपये के भुगतान और बिचौलियों की भूमिका सामने आने के बाद मामला केवल एक संदिग्ध मौत तक सीमित नहीं रह गया है।

इस घटना ने मालवा-निमाड़ में वर्षों से चल रहे उस विवाह तंत्र को भी चर्चा में ला दिया है, जिसमें दूसरे राज्यों की युवतियों का विवाह स्थानीय युवकों से बिचौलियों के जरिए कराया जाता है। जून में पिपलौदा के सुखेड़ा और सरवन क्षेत्र के दो युवकों की शादी उत्तर प्रदेश की युवतियों से कराई गई, लेकिन दोनों दुल्हनें एक माह के भीतर ही घर छोड़कर चली गईं। इसके बाद पीड़ित परिवारों ने धोखाधड़ी और ठगी के मामले दर्ज कराए।

दूसरे राज्यों में विवाह का चलन बढ़ा

रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों की युवतियों से विवाह कराने का चलन बढ़ा है। अधिकांश मामलों में वर-वधु पक्ष पहले से एक-दूसरे को जानते तक नहीं हैं। पूरा संपर्क स्थानीय और अंतरराज्यीय दलालों के माध्यम से होता है।

दूल्हा पक्ष से लेते हैं रुपये

दूल्हा पक्ष से ढाई से पांच लाख रुपये, कई मामलों में इससे अधिक राशि ली जाती है। इस रकम का बड़ा हिस्सा बिचौलियों के बीच बंट जाता है, जबकि युवती के परिवार तक अपेक्षाकृत कम राशि पहुंचती है। इन विवाहों में सबसे बड़ी समस्या पहचान और दस्तावेजों के समुचित सत्यापन का अभाव है। कई बार विवाह मंदिरों, धर्मशालाओं या होटलों में करा दिए जाते हैं और उनका विधिवत पंजीयन भी नहीं कराया जाता।

युवती के वास्तविक स्वजन, स्थायी पते और पहचान की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। विवाद की स्थिति में पीड़ित परिवार के लिए युवती या उसके वास्तविक परिवार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पुलिस रिकार्ड में ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें विवाह के कुछ दिन या सप्ताह बाद ही दुल्हन के नकदी और जेवर लेकर चले जाने की शिकायतें दर्ज हुई हैं। विवाह कराने वाले दलालों ने लाखों रुपये लेने के बाद संपर्क समाप्त कर दिया।

मानव तस्करी के पहलुओं की जांच जरूरी

शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान के अनुसार हर अंतरराज्यीय विवाह मानव तस्करी का मामला नहीं होता, लेकिन बिना सत्यापन और बिचौलियों के माध्यम से होने वाले ऐसे विवाह संगठित अपराधी नेटवर्क के लिए अवसर बन सकते हैं।

यदि किसी युवती को झूठे वादों, धोखे या आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर दूसरे राज्य लाया गया हो, उसकी पहचान छिपाई गई हो या उसके बदले आर्थिक लेन-देन हुआ हो, तो ऐसे मामलों में मानव तस्करी के पहलुओं की भी जांच आवश्यक हो जाती है। रतलाम के मामले में भी संध्या कुमारी के स्वजनों से पुलिस संपर्क नहीं कर सकी है और बिचौलिए फरार है।

दूसरे राज्यों की पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है

शादी के नाम पर ठगी करने वाले दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में अंतरराज्यीय पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। हाल ही में हुए मामलों की जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। - निमिष अग्रवाल, डीआईजी रतलाम रेंज।

मर्डर केस: पत्नी को मारकर रातभर जागता रहा पति

माही की गूंज, रतलाम।

सोनार बावड़ी में पत्नी रुकैया की नृशंस हत्या के मामले में सोमवार को आरोपित असगर अली को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उधर पोस्टमार्टम के बाद रविवार देर रात रुकैया का शव सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वारदात से पहले असगर अली पत्नी को लांग ड्राइव पर चलने के लिए कह रहा था।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपित का कहना है कि गुस्से में उसे होश नहीं रहा और उसने वारदात कर दी। हालांकि पुलिस इस बयान की अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी पुष्टि कर रही है। पुलिस हिरासत के दौरान आरोपित असगर का व्यवहार भी सामान्य नहीं दिखा। पूछताछ के दौरान वह लगातार दीवार को एकटक घूरता रहा। उसने पूरी रात आंख नहीं मूंदी और काफी समझाने के बाद केवल आधी रोटी ही खाई।

मुझे रुकैया से मिला दो

वह बार-बार केवल एक ही बात दोहराता रहा मुझे रुकैया से मिला दो और रोता रहा। पूछताछ में वह यह भी कहता रहा कि पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वह बाबा, दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों पर गया था तथा वर्तमान में उसका दिमागी इलाज चल रहा था।

स्वजन असगर के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उपचार संबंधी कोई चिकित्सीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसे में मानसिक बीमारी के दावे की भी जांच की जा रही है।

रुकैया की हत्या की बर्बरता और उसके बाद आरोपित पति के व्यवहार ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।

पहले खेतों में नीलगाय दिखती थी... इस बार दिखा कूनो से निकला चीता!

श्योपुर।

जिले के सोईकलां इलाके में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है, तो वह कोई नेता नहीं, कोई फिल्म स्टार नहीं... बल्कि एक चीता है। वही चीता, जिसे कुछ साल पहले बड़े इंतजार और उम्मीदों के साथ कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। अब वही चीता जंगल की सीमा पार करके गांव के खेतों तक पहुंच गया है। और पिछले तीन दिनों से ग्रामीणों की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं।

वाक्या गुरुनावदा गांव का है। यहां पिछले तीन-चार दिनों से लोगों को खेतों में एक चीता दिखाई दे रहा है। कभी वह मेड़ों के बीच दौड़ता नजर आता है। कभी फसलों के किनारे टहलता हुआ। कभी दूर से झाड़ियों में गायब हो जाता है। जिसने भी उसे देखा, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर मोबाइल निकला... वीडियो बना... और देखते ही देखते पूरा गांव उस वीडियो की चर्चा करने लगा।

कुछ लोग उत्साहित हैं कि उन्होंने पहली बार खुले में चीता देखा। तो कुछ लोग डरे हुए हैं कि अब खेतों में अकेले कैसे जाएं? आखिर खेती भी करनी है। मवेशियों को भी चराना है। लेकिन अगर सामने अचानक चीता आ गया तो? इसी डर ने गांव में बेचैनी बढ़ा दी है। चीते की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी हरकत में आ गई। ट्रैकिंग टीमें लगातार उसके मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। यह देखा जा रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है और कहीं किसी आबादी के ज्यादा करीब तो नहीं पहुंच रहा।

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर. थिरुकुराल का कहना है कि खुले जंगल में रहने वाले चीते स्वाभाविक रूप से बड़े इलाके में घूमते हैं। विभाग लगातार उनकी निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी तैनात की जाएंगी। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले खेतों में न जाएं, खासकर सुबह और शाम के समय अधिक सतर्क रहें। यदि कहीं चीता दिखाई दे, तो उसके पास जाने या उसे घेरने की कोशिश न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें।

दरअसल, कूनो नेशनल पार्क में इस समय 19 चीते खुले जंगल में घूम रहे हैं, जबकि 31 चीते अभी बाड़ों में हैं। इनकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। कभी-कभी कोई चीता अपने नेचुरल बिहेवियर की वजह से तय सीमा से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में भी पहुंच जाता है। लेकिन गांव वालों के लिए यह कोई सामान्य बात नहीं है। उनके लिए यह पहली बार है, जब खेत में फसल के साथ-साथ चीते की मौजूदगी का भी ध्यान रखना पड़ रहा है।

एक तरफ खेत हैं... दूसरी तरफ जंगल... और दोनों के बीच घूमता एक चीता

गुरुनावदा और आसपास के गांवों में लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कूनो का यह मेहमान आखिर कब वापस जंगल लौटेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। श्योपुर के इन गांवों में पिछले तीन दिनों से सुबह की शुरुआत अब मौसम या खेती की चर्चा से नहीं... बल्कि इस सवाल से हो रही है कि आज चीता कहां दिखा?

निकाह करके किन्नर को साथ रखा, 13 लाख से अधिक रुपए भी लिए

माही की गूंज, शाजापुर।

शहर के कोतवाली थाने में एक किन्नर ने मुस्लिम युवक और उसके स्वजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। किन्नर का आरोप है कि युवक ने उससे निकाह किया, फिर मकान और आटो खरीदने के नाम पर 13 लाख रुपये से अधिक रकम ली और बाद में उसे छोड़ दिया।

किन्नर ने युवक के स्वजन पर प्रताड़ना और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित किन्नर के मुताबिक पटेलबाड़ी निवासी आरोपित मुशर्रफ मंसूरी से उसकी पहचान इंटरनेट प्लेटफार्म पर हुई थी। नजदीकियां बढ़ने पर उसने शारीरिक संबंध बनाए और शादी का प्रस्ताव दिया। कहा कि शाजापुर में पत्नी की तरह रखेगा।

इंदौर में मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह किया। बाद में किन्नर से 13 लाख रुपये से अधिक की राशि ली लेकिन किन्नर ने जब रुपये वापस मांगे, तो मुशर्रफ ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।

किन्नर ने बताया कि उसने सोने की चेन और अन्य सामान बेचकर मुशर्रफ को रुपये दिए थे। उसने यह आरोप भी लगाया कि निकाह के बाद मुशर्रफ ने उसका ऑपरेशन करवाकर आवाज बदलवाई थी। उसके स्वजन से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने भी जान से मारने की धमकी दी। पुलिस भी पहले अनसुना करती रही।

कई दिन तक थाने के चक्कर लगाने के बाद उसने मुशर्रफ, उसके पिता जाकिर मंसूरी व मां फेमिदा मंसूरी और भाई अल्फेज मंसूरी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

सांप के काटने पर परिजन डिब्बे में जिंदा सांप भी लेकर पहुंच

माही की गूंज, मंदसौर।

जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां कुछ लोग एक घायल युवक के साथ एक जहरीले सांप को भी डिब्बे में बंद करके ले आए। बताया जा रहा है कि, युवक को सांप ने डंस लिया था, जिसके बाद परिजन मरीज के साथ-साथ उसी जिंदा सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर सीधे अस्पताल ले आए। ये मंजर देख अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों के साथ साथ अन्य लोग भी दंग रह गए।

बताया जा रहा है कि, मामला मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले राजनगर का है। यहां एक युवक को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। घटना के तुरंत बाद परिजन युवक को इलाज के लिए मंदसौर जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए। इसी बीच उन्हें किसी ने बताया कि, अगर सांप की पहचान करा दी जाए तो समय रहते डॉक्टरों द्वारा उचित एंटी वेनम देकर रीज को बचाया जा सकता है। इसपर परिजन ने उस सांप को भी पकड़ लिया, जजिसने युवक को काटा था।

घर वाले प्लास्टिक के डिब्बे में ले आए सांप

यही नहीं, उसकी नस्ली शिनाख्त बताने के बजाए वो सांप को ही एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके मरीज के साथ अस्पताल ले आए। मरीज के परिजन की इस हरकत ने अस्पताल में मौजूद हर किसी को दंग जरूर कर दिया, लेकिन परिजन का मानना था कि, जिस तरह उन्हें जानकारी मिली है कि, सांप को देखकर डॉक्टर ये आसानी से पहचाना जा सकता है कि, वो कितना जहरीला है। उसी हिसाब से उसका सही एंटी-वेनम (एंटी स्नेक वेनम) और इलाज दिया जा सकता है। सिर्फ इसी उद्देश्य के तहत वो सांप को साथ लाए हैं।

डॉक्टर बोले- ऐसा करना खतरनाक

हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज का इलाज तो शुरू कर दिया है। साथ ही, सांप को देखकर समय रहते मरीज को उचित उपचार भी दिया जाने लगा है। लेकिन, चिकित्सकों के साथ साथ वन्यजीव विशेषज्ञों ने परिजन द्वारा किए गए इस कार्य को बेहद जोखिम भरा और खतरनाक बताया। सांप को डसने के बाद पकड़ने की कोशिश करना या उसे अस्पताल लाना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। वहीं, सर्प विशेषज्ञों के अनुसार, किसी को काटने के बाद सांप सामान्य तौर पर बेहद आक्रामक और गुस्सैल हो जाता है, जिससे आसपास के अन्य लोगों को भी उसके डसने का गंभीर खतरा बढ़ जाता है।

डॉक्टरों की अपील

वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि, वैसे बारिश के दिनों में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं, सांप द्वारा काटे जाने की स्थिति में बिना समय गंवाए मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की चिंता करें। ये बात सही है कि, सांप को देखकर उसका उचित एंटी वेनम दिया जा सकता है। लेकिन, जिंदा सांप को पकड़कर अस्पताल लाने का जोखिम उठाने के बजाय अगर तत्काल ही संभव हो तो सुरक्षित दूरी से उसकी फोटो या वीडियो बना लें। ताकि, मरीज को दिए जाने वाले इलाज में सहायता मिल सके।

पटवारी नपती करने आए तो सही, पैर काट दूंगा- पूर्व भाजपा विधायक

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले की सुवासरा सीट से भाजपा विधायक रहे राधेश्याम पाटीदार का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में वह अपनी ही सरकार के सिस्टम को चुनौती देते हुए तहसीलदार और पटवारी को गाली दे रहे हैं।

पूर्व विधायक पाटीदार ने स्थानीय बोली (मालवी) में यह भी कहा कि पटवारी यहां नपती करने आए तो सही उनके पैर काट देंगे। हालांकि, बाद में उन्होंने सफाई दी कि वीडियो में काट-छांट की गई है।

जमीन विवाद को लेकर बढ़ा तनाव और गंभीर आरोप

पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ग्राम गुराड़िया प्रताप में रहते हैं। उनके गांव के पास ग्राम सेमली कांकड़ में सर्वे नंबर पांच और सात की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मामला एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच दूसरे पक्ष के परमानंद पाटीदार, कालूराम पाटीदार और बद्रीसिंह परिहार ने पूर्व विधायक राधेश्याम व उनके स्वजन पर जमीन कब्जे की कोशिश, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

बताया कि बंदोबस्त के बाद से त्रुटिपूर्ण नक्शे के कारण विवाद की स्थिति बनी। बद्रीसिंह ने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा अपनी प्रशासनिक पहुंच और धौंस दिखाते हैं। कहते हैं कि कलेक्टर-एसपी भी यहां दौड़ते हुए आएंगे।

पूर्व विधायक का पक्ष: वीडियो में काट-छांट का लगाया आरोप

वहीं पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने कहा कि उनका वीडियो काट-छांट कर प्रसारित किया गया है। एक किसान 1954 से इसी भूमि पर खेती कर रहा है लेकिन कुछ लोग शासकीय पट्टाधारी से जमीन खरीदकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।

अफसर से बदसलूकी, नोटिस फाड़कर बोले नेताजी- तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में डोसीगांव मल्टी का विवाद लगातार जारी है। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी के रहवासियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महू नीमच रोड़ पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी नगर निगम के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इधर डोसी गांव मल्टी को खाली कराने पहुंचे निगम प्रशासन और पुलिस अमले का जबर्दस्त विरोध हुआ। पूर्व महापौर पारस सकलेचा ने नोटिस फाड़कर निगम आयुक्त को नौकरी खा जाने की धमकी दी।

डोसीगांव मल्टीवासी रिमझिम बारिश में भी सड़क पर बैठे रहे और नगर निगम के विरोध में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान मुख्य कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया। यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक ओर 208 घरों के निवासी सड़क पर हैं तो दूसरी ओर प्रशासन भी परेशान है।

पूर्व महापौर ने नोटिस फाड़े, निगम आयुक्त से कहा- नौकरी खा जाऊंगा

इस बीच डोसीगांव मल्टी में हंगामा जारी है। मल्टी को खाली कराने पहुंचे निगम प्रशासन और पुलिस अमले का लोगों ने विरोध किया। इसी दौरान पूर्व महापौर पारस सकलेचा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने निगम आयुक्त के हाथ से नोटिस छीनकर फाड़ दिए और कहा कि एकतरफा कार्रवाई कर रहे हो, आपकी नौकरी खा जाऊंगा। मौके पर तनाव के बाद पुलिस ने हालात संभाले।

इधर डोसीगांव मल्टी के बकायादारों पर निगम की चेतावनी का असर दिखने लगा है। अब तक करीब दो दर्जन लोग आवास खाली कर चुके हैं। निगम की 206 हितग्राहियों को बकाया राशि जमा करने और नहीं करने पर कब्जा हटाने की निगम के अल्टीमेटम की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई। कुछ बकायादारों का कहना है कि वे एकमुश्त राशि देने में सक्षम नहीं हैं। किस्तों में राशि जमा करवाने को तैयार है।

निगम आयुक्त अनिल भाना ने कब्जा हटाने की कार्रवाई करने के लिए निगम के दो दर्जन से ज्यादा अफसरों और लगभग दो सौ कर्मचारियों का जंबो दल गठित किया है। दल में राजस्व, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पीएम आवास योजना सहित तमाम विभागों के अफसर और कर्मचारियों को शामिल किया है।

जो लोग पूरी राशि जमा करवा रहे हैं उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे

रतलाम नगर निगम आयुक्त अनिल भाना का कहना है कि हम भी नहीं चाहते कि किसी की छत छीनें परंतु शासन के निर्देश है कि पूरी राशि जमा करवाएं। जो लोग पूरी राशि जमा करवा रहे हैं उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे। जो नहीं जमा करवा रहे हैं उनसे राशि जमा करवाएंगे।

ओंकारेश्वर के होटल में जुंआ खेलत 8 लोग गिरफ्तार, 68 हजार रुपये जप्त

माही की गूंज, खंडवा।

ओंकारेश्वर स्थित एक होटल में पुलिस ने मंगलवार देर रात छापामार कार्रवाई कर जुआ खेलते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मांधाता विधायक नारायण पटेल के प्रतिनिधि शिवचरण रावत भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 68 हजार रुपए नकद और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि ओंकारेश्वर स्थित होटल त्रिनेत्रम के कक्ष क्रमांक 406 में कुछ लोग हार-जीत का दांव लगाकर ताश खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस दल ने होटल में दबिश दी और मौके से आठ लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में शिवचरण रावत निवासी ब्रह्मपुरी, गोपीचंद यादव निवासी बालवाड़ी, मोहन गांगलेकर, भगवानप्रसाद मिश्रा, मुकेश गोलकर, वृंदावन उर्फ महेश पाठक, योगेश चौबे तथा अभिषेक अत्रे शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 68 हजार रुपए नकद जब्त किए हैं।

कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार लोगों में भाजपा नेता एवं विधायक प्रतिनिधि शिवचरण रावत का नाम सामने आने से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। रावत वर्तमान में विधायक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा पूर्व में नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अधिकांश लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।

घटना को लेकर यह भी चर्चा है कि होटल में जन्मदिन के अवसर पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई और मौके पर जुआ खेलते पाए गए लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार होटल का पंजीकृत स्वामी भी आरोपियों में शामिल है। वहीं एक अन्य व्यक्ति के मौके पर नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

करंट लगने से गाय की मौत, गौरक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन

माही की गूंज, खरगोन।

मूसेखा रोड पर मंगलवार रात करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। घटना के बाद गौरक्षकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रात करीब नौ बजे गुरुनानक चौराहे पर जेसीबी की सहायता से गाय का शव सड़क पर रखकर विद्युत कंपनी की कथित लापरवाही के खिलाफ धरना दिया गया।

प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी हुई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मार्ग अवरुद्ध कर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला। सूचना मिलने पर एसडीएम सत्येंद्र बैरवा, कोतवाली थाना प्रभारी बी.एल. मंडलोई सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की।

गौरक्षक दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल लिखित कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं विद्युत कंपनी के अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरक्षक समिति अध्यक्ष सतीश राठौर ने बताया कि इससे पूर्व मांगरूल रोड पर भी करंट लगने से एक नंदी की मौत हुई थी, लेकिन उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कम समय के भीतर करंट से पशुओं की मौत की यह दूसरी घटना है, जो विद्युत व्यवस्था में गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री सौरभ साहू ने बताया कि मृत गाय का परीक्षण कराया जाएगा तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैंककर्मी बनकर युवती से 75 हजार रुपए की साइबर ठगी

माही की गूंज, बुरहानपुर।

जिले में साइबर ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर एक युवती से 75 हजार 147 रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने बैंक में दर्ज शिकायत की जानकारी देकर युवती का विश्वास जीता और राशि वापसी के नाम पर एक संदिग्ध मोबाइल अनुप्रयोग फाइल भेज दी। फाइल स्थापित करने के कुछ ही समय बाद युवती के खाते से तीन बार में राशि निकाल ली गई। मामले में जिला साइबर प्रकोष्ठ की जांच के बाद शिकारपुरा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार शिकारपुरा थाना क्षेत्र के राजपुरा गेट निवासी युवती का खाता बैंक ऑफ इंडिया की अमरावती रोड शाखा में है। 2 मई 2026 को वह एक एटीएम से पांच हजार रुपए निकालने गई थीं। मशीन से राशि नहीं निकली, लेकिन उनके खाते से रकम कट गई। इस संबंध में युवती ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई थी।

बताया गया कि 11 जुलाई को युवती के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को बैंक की मुंबई शाखा का कर्मचारी बताते हुए खाते से कटी राशि वापस दिलाने का आश्वासन दिया। शिकायत से जुड़ी जानकारी बताने पर युवती को उसकी बात पर विश्वास हो गया।

इसके बाद आरोपी ने संदेश माध्यम से अपनी कथित पहचान संबंधी जानकारी और एक मोबाइल अनुप्रयोग फाइल भेजी तथा उसे स्थापित करने के लिए कहा। युवती ने निर्देशानुसार फाइल स्थापित कर आवश्यक जानकारी दर्ज कर दी। इसके कुछ समय बाद उसके खाते से लगातार तीन बार में 25 हजार, 25 हजार और 25 हजार 147 रुपए निकाल लिए गए।

ठगी का पता चलते ही युवती ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई तथा बैंक खाते को तत्काल अवरुद्ध कराया। जिला साइबर प्रकोष्ठ द्वारा की गई तकनीकी जांच के बाद प्राप्त शून्य प्राथमिकी के आधार पर शिकारपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबर, बैंक लेनदेन और भेजी गई मोबाइल अनुप्रयोग फाइल की तकनीकी जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि ठगी की राशि किन खातों में स्थानांतरित की गई और इस पूरे मामले में कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते, एटीएम कार्ड, पिन, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक अथवा मोबाइल अनुप्रयोग फाइल को डाउनलोड करने से बचें तथा ऐसी स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

खेल मैदान की बदहाल स्थिति के विरोध में छात्र-खिलाड़ियों ने निकाला पैदल मार्च

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के छात्र एवं खिलाड़ियों ने बुधवार को खेल मैदान की खराब स्थिति के विरोध में कॉलेज से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान खिलाड़ियों ने डिप्टी कलेक्टर शक्ति सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर खेल मैदान के जीर्णोद्धार, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया कि शहर का प्रमुख खेल मैदान लंबे समय से रखरखाव के अभाव में उपेक्षा का शिकार है। मैदान में गैर-खेल गतिविधियों के आयोजन से खिलाड़ियों को अभ्यास में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। खिलाड़ियों ने 400 मीटर दौड़ पथ पर संकेतांकन कराने, जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने, मैदान में निजी आयोजनों एवं वाहन खड़े करने पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए शौचालय, स्नानगृह, खेल सामग्री रखने के लिए भंडार कक्ष तथा रखरखाव हेतु स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग भी की गई। ज्ञापन में मैदान की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने तथा प्रवेश द्वारों सहित पूरे परिसर में निगरानी कैमरे लगाने की मांग भी शामिल रही। डिप्टी कलेक्टर शक्ति सिंह चौहान ने ज्ञापन प्राप्त कर खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए मरीजों को उठानी पड़ रही परेशानी

माही की गूंज, बड़वानी।

जिला अस्पताल में परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने आने वाले मरीजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए अस्पताल में पेयजल, बैठने तथा ठहरने जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इसके कारण कई लोगों को खुले में रात बितानी पड़ रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में सप्ताह में सीमित संख्या में ही परिवार नियोजन ऑपरेशन किए जाते हैं। निर्धारित संख्या पूरी होने के बाद अन्य मरीजों को अगली तिथि दी जाती है या फिर वापस लौटना पड़ता है। इससे मरीजों का समय और आर्थिक संसाधन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार सुबह छह बजे से नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होती है और सीमित संख्या में ही मरीजों का चयन किया जाता है। इसके चलते दूर-दराज से आने वाले कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिले के सभी विकासखंडों में नियमित शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि लोगों को बार-बार जिला अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि पूर्व पंजीयन वाले हितग्राहियों को ही बुलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में जिले के सभी विकासखंडों में परिवार नियोजन शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।

ढाई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ

माही की गूंज, खरगोन।

शहर में बुधवार को ढाई करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक सब्जी मंडी शेड की आधारशिला रखी तथा नगर पालिका द्वारा खरीदे गए 10 नए कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि आधुनिक सब्जी मंडी शेड के निर्माण से व्यापारियों और किसानों को बारिश तथा तेज धूप से राहत मिलेगी। मंडी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान शहर के चार वार्डों में सीमेंट-कांक्रीट सड़कों के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। इन सड़कों के निर्माण से पांच हजार से अधिक नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 10 नए कचरा संग्रहण वाहन खरीदे गए हैं। इन वाहनों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। इनके संचालन से शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और गति मिलेगी।

विधायक पाटीदार ने कहा कि प्रमुख बाजारों और व्यस्त क्षेत्रों में रात्रिकालीन नियमित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे दिन के समय यातायात एवं व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। इससे शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं के विस्तार और शहर के समग्र विकास के लिए ऐसे विकास कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

कार्यक्रम में नगर पालिका सीएमओ कमला कौल, स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते, लोक निर्माण समिति सभापति धीरेंद्रसिंह चौहान सहित जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

बदलता भूजल प्रवाह बढ़ाता भवनों के लिए जोखिम

पर्वतीय भूमिगत जल भंडारों पर वैश्विक स्तर पर भी बहुत विस्तृत अध्ययन कई कारणों से नहीं हो पाया है। उत्तराखंड जैसे घोषित पर्वतीय राज्य में भी यही स्थिति है। किंतु जोशीमठ भूधंसाव से बनी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं तथा पहाड़ी नए-पुराने शहरों को बचाने-बसाने के क्रम में भूजल विज्ञान की जमीनी समझ अपरिहार्य हो गई है।

जोशीमठ में 2 जनवरी, 2023 से एक कॉलोनी के चौनल से पानी निकलने की सूचना मिलने के बाद से ही सरकारी स्तर पर इसकी प्रतिदिन माप की जा रही है और तब से जलप्रवाह में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। बयान जारी होते रहे हैं कि पानी के प्रवाह की दर इतनी कम हुई या इतनी ज्यादा हुई, या अब एकदम ही बंद हो गई है। पानी लोगों के घरों में भी दरारों के साथ आया था। ऐसे बयानों से आमजन के बीच यह धारणा विकसित करने की कोशिश होती है कि कम होता डिस्चार्ज भूधंसाव का जोखिम कम होने का सूचक है। ऐसा विश्लेषण करना वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं होगा। यदि निर्माणों को आधार देने वाली परतों में जल रिसाव या जल निकासी घटती-बढ़ती रहती है अथवा चट्टानों के अपभ्रंशों में पानी सूखता-भरता रहता है, यानी उतार-चढ़ाव होता है, तो आधारित भवनों की नींवों पर काफी दबाव आ जाता है।

भूजल की तेजी से अप्रत्याशित घटत-बढ़त भवनों को लंबी अवधि में कमजोर ही करती है। यदि यह बाहर निकलता कम पानी पहले कहीं नींवों के आसपास जमा होने के कारण कम हो रहा है, तो वह भवनों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। नींव के आसपास जमा पानी मृदा परतों की ताकत कम कर देता है। पहाड़ों में, खासकर चूने के अपभ्रंशों में भी पानी घुसता व जमा होता है। ठोस चट्टानों की दरारों से भी पानी घुसता है। घने जंगलों के चौड़ी पत्तियों वाले क्षेत्र में भी भूमिगत जल जमा होता है। रिसाव बर्फबारी से भी संभव है।

अनुभव रहा है कि जब कभी अचानक नदी की धारा मंद हो जाती है, तो अंदेशा पैदा हो जाता है कि कहीं ऊपर नदी मार्ग में भूस्खलनों से अवरोध आ गया है। अब पानी कम दिख रहा है, किंतु जब वह अवरोध टूटेगा, तो नदी भीषण वेग में आ सकती है। जलवायु बदलाव की अतिरेकी घटनाओं के बीच ऐसे दंश बढ़ेंगे ही।

कई बार गहराइयों तक पहुंची नींवों से भी पहाड़ों में जमीन के अंदर ढलानों में बहता जल-प्रवाह बाधित हो जाता है। ऐसे में जलधाराएं अन्य राहें ढूंढ़ लेती हैं व अन्य कमजोर भ्रंशों से फूटकर बाहर निकल सकती हैं। जमीन के भीतर यदि ढीली मिट्टी-पत्थर की परतें हों, तो जैसे सतह पर ढलानों में वेगमयी जल-प्रवाह मलबा-मिट्टी लेकर बढ़ता है, वैसे ही वे जमीन के भीतर भी मिट्टी-पत्थर लेकर बढ़ सकते हैं और मकानों, भवनों व पिलरों की नींव की मिट्टी बहाकर आगे ले जा सकते हैं। नींव के मेटिरियल के कटाव से मकान, भवन, पुल आदि तिरछे या ध्वस्त हो सकते हैं। यदि भवनों के आसपास किन्हीं कारणों से दरारें आ जाएं, तो भूमिगत नींवों के पास पहुंचा पानी भी मकानों, भवनों या अन्य कंक्रीट ढांचों को असुरक्षित व जर्जर बना सकता है।

निर्माण संरचनाओं की नींवों के जितना निकट भूमिगत जल स्तर होता जाता है, उतनी ही नींव की भवन धारण क्षमता घटती जाती है। भूमिगत जल जितना नीचे होगा, उतना ही कम उसका असर निर्माण संरचनाओं पर पड़ेगा। शैल या मृदा परतों के रंध्रों में पहुंचा पानी पोर प्रेशर पर असर डालता है। यदि रंध्रों में पानी हवा को हटाकर अपनी जगह बना रहा है, तो पानी, वायु से भारी होने के कारण, शैल या मिट्टी की परतों का भार बढ़ा देता है। इससे सतह व भीतर के ढलावों (स्लोप्स) में अस्थिरता आ जाती है, जिससे निर्माणों में भी अस्थिरता आ सकती है। साथ ही, पानी जब किसी शैल या मृदा परत पर रिसता रहता है, तो वह उस परत के भौतिक व रासायनिक घटकों में बदलाव ले आता है।

यदि शौचालय सीवर लाइनों से जुड़े नहीं हैं और उनका मल-मूत्र एवं शौच-जल परिसर में बने पिटों में ही जाता है, तो अत्यधिक उपयोग की स्थिति में भूमि के भीतर नींवों के आसपास रिसाव और जल-जमाव की समस्या पैदा हो सकती है। अधिकांश गांवों व बस्तियों में शौचालय सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, इसलिए यह जोखिम वहां भी विद्यमान है। ऐसे में यदि किसी स्थान पर सामान्य क्षमता से अधिक भीड़ शौचालयों और मूत्रालयों का उपयोग करे, तो पिटों पर अत्यधिक दबाव पड़ना, उनका क्षतिग्रस्त होना तथा रिसाव की समस्या बढ़ना स्वाभाविक है।

पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों के निर्माण के लिए गहरी नींव आवश्यक होती है, जिससे भूमिगत जलवाहिनियों को क्षति पहुंचने या उनके प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन की आशंका बढ़ जाती है। जोशीमठ जैसे क्षेत्रों में वर्षों से जारी असमान भू-धंसाव के कारण सतही और भूमिगत जल के प्रवाह तथा रिसाव की दिशा भी बदल सकती है। जिन इलाकों में भू-धंसाव हो रहा है, वहां खासकर बरसात में अधूरी नालियां या अन्य प्रकार के खदान के काम नहीं छोड़े जाने चाहिए। यदि नदियों में, बैराज-बांधों में, सुरंगों के मुहानों पर मलबे के अंबारों के अवरोध खड़े कर दिए हों, तो उनसे भी पानी रिसकर पार्श्व की संरचनाओं में जा सकता है।

वीरेन्द्र कुमार

जोशीमठ धंसाव से जुड़ी सरकारी उपग्रह तस्वीरें भले ही सार्वजनिक वेबसाइट से हटा दी गई हों, लेकिन ग्रीस के एक शोध संस्थान के सैटेलाइट विश्लेषण, जिसे भारत के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन ने प्रकाशित किया, के अनुसार 2018 से 31 दिसंबर, 2022 तक जोशीमठ औसतन लगभग 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से धंसता रहा।

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन का काम तेज

माही की गूंज, धार।

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के अंतर्गत निर्माणाधीन इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रहा है। 03 अगस्त 2026 तक की प्रगति के अनुसार सुरंग निर्माण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

2957 मीटर सुरंग में लाइनिंग पूरी, बैलास्टलेस ट्रैक बिछाने का काम जारी

पश्चिम रेलवे के अनुसार सुरंग निर्माण में सुरंग खुदाई के उपरांत लाइनिंग का कार्य सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है, जो सुरंग को स्थायित्व, मजबूती एवं दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है। परियोजना के अंतर्गत 2957 मीटर लंबी सुरंग में लाइनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके बाद सुरंग के भीतर बैलास्टलेस ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

ट्रैक और सीमेंट कंक्रीट कार्य की स्थिति

अब तक 1216 मीटर बैलास्टलेस ट्रैक का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा पीसीसी (प्लेन सीमेंट कंक्रीट) फाइनल लेयर का 1470 मीटर तथा पीसीसी फर्स्ट लेयर का 2007 मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में 810 मीटर में बैलास्टलेस ट्रैक एवं 740 मीटर पीसीसी निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ड्रेनेज और कट एंड कवर सेक्शन का कार्य अंतिम चरण में

सुरंग में जल निकासी (ड्रेनेज) व्यवस्था को भी समानांतर रूप से विकसित किया जा रहा है। दोनों ओर की साइड ड्रेन, इनवर्ट ड्रेन तथा अन्य संरचनात्मक कार्यों का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त कट एंड कवर सेक्शन में ओवर्ट रीइन्फोर्समेंट एवं लाइनिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

आधुनिक सुरक्षा तंत्रः वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था

सुरंग को सुरक्षित एवं आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूज निच), बचाव एवं राहत कार्यों हेतु रेस्क्यू शाफ्ट तथा ताजी हवा के आवागमन के लिए वेंटिलेशन डक्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। सुरंग के अंदर सफोकेशन को दूर करने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। ये सभी संरचनाएं भविष्य में सुरंग के सुरक्षित संचालन एवं आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी।

समयबद्ध निर्माण के लिए आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल

पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा सुरंग के शेष हिस्से में ड्रेनेज, बैकफिलिंग तथा अन्य सिविल कार्यों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए आधुनिक मशीनरी एवं उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच मजबूत होगा रेल संपर्क

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पूर्ण होने के बाद मध्य प्रदेश एवं गुजरात के बीच रेल संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा। इससे यात्रियों को बेहतर एवं तेज रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं माल परिवहन को नई गति मिलने के साथ क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक विकास को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।

अपूर्ण आवासों की जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित

माही की गूंज, आलीराजपुर।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत तृतीय किश्त प्राप्त होने के 45 दिवस बाद भी अपूर्ण पड़े आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के उद्देश्य से जिला पंचायत कार्यालय में 3 एवं 4 अगस्त को जिला स्तरीय हितग्राही पेशी एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संघमित्रा गौतम ने 925 अपूर्ण आवासों के हितग्राहियों की प्रगति की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान ऐसे हितग्राहियों को सख्त निर्देश दिए गए जिन्होंने जानबूझकर अथवा उदासीनता के कारण आवास निर्माण पूर्ण नहीं किया या तृतीय किश्त की राशि का अन्य कार्यों में उपयोग किया गया। जिन आवासों का निर्माण वर्षाकाल में पूरा किया जा सकता है, उन्हें एक से दो माह की समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं जिन स्थानों पर फसल अथवा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण निर्माण सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे हितग्राहियों को फसल कटाई के बाद नवंबर-दिसंबर तक आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कई हितग्राहियों ने एक माह के भीतर छत डालकर शेष कार्य पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती संघमित्रा गौतम ने बताया कि हितग्राहियों को जारी किए गए सूचना पत्रों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। 925 अपूर्ण आवासों में से 203 आवासों में हितग्राहियों द्वारा छत डाल दी गई है तथा वे पूर्ण हो चुके हैं अथवा शीघ्र पूर्ण होने की स्थिति में हैं। इनमें जनपद आलीराजपुर के 69, चंद्रशेखर आजाद नगर के 11, जोबट के 18, कट्ठीवाड़ा के 19, सोंडवा के 81 तथा उदयगढ़ के 5 आवास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता राशि का समयबद्ध एवं उचित उपयोग सुनिश्चित कर हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराना है।

बैठक में समग्र ई-केवाईसी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिन ग्राम पंचायतों में समग्र ई-केवाईसी एवं आवास निर्माण दोनों की प्रगति अत्यंत कम पाई गई, वहां के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों का जुलाई 2026 का वेतन एवं पारिश्रमिक प्रगति में सुधार होने तक रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के बैठक से अनुपस्थित रहे 33 सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों का एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए।

ग्रामीण नलजल योजना पर सरपंच-सचिवों का प्रशिक्षण आयोजित

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संघमित्रा गौतम की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में ग्रामीण नलजल योजना के संचालन, संधारण एवं प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल तथा मध्य प्रदेश जल निगम, भोपाल के तत्वावधान में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा मध्य प्रदेश जल निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्ध गोपाल वर्मा ने मध्य प्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नियम प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू होंगे। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व, वॉल्व सह पंप ऑपरेटर की भूमिका, जल प्रभार निर्धारण एवं संग्रहण, दंड एवं पेयजल आपूर्ति स्थगन की प्रक्रिया, नियोजन एवं वित्तीय व्यवस्था, नवीन जल कनेक्शन एवं कनेक्शन विच्छेदन, पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया गया। इसमें पानी के पीएच (श्च॥), हार्डनेस तथा फ्लोराइड परीक्षण का लाइव डेमोंस्ट्रेशन कर प्रतिभागियों को गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति तक शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ग्राम पंचायतों का भी प्राथमिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ गांवों की स्वच्छता बनाए रखना भी पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।उन्होंने सरपंचों एवं सचिवों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर पानी जमा न होने दें।जहां पानी जमा हो, वहां समय-समय पर तेल का छिड़काव कराया जाए ताकि मलेरिया एवं डेंगू के मच्छरों का लार्वा विकसित न हो। उन्होंने कचरे के वैज्ञानिक एवं उचित निस्तारण के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित करने के निर्देश दिए।उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट-बाजारों में खाद्य सामग्री को ढंककर रखने, स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर तरीके से खाद्य पदार्थों का विक्रय सुनिश्चित कराने तथा खाद्य स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने सभी ग्राम पंचायतों से आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित होने का अनुरोध करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत भवनों को भी आदर्श स्वरूप प्रदान किया जाए। उन्होंने पंचायत भवनों में बच्चों के लिए पुस्तकालय (लाइब्रेरी) स्थापित करने की दिशा में भी आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्रीमती माथुर द्वारा ग्राम पंचायत सरपंचों को वाटर टेस्ट किट का प्रदाय किया गया।

जनसुनवाई का सकारात्मक असर

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले में आयोजित जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का सशक्त माध्यम बन रही है। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशों पर जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ निराकरण किया जा रहा है, जिससे पात्र हितग्राहियों को शीघ्र राहत मिल रही है।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत नानपुर निवासी शांतीबाई को शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलने संबंधी आवेदन को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग द्वारा उनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत कराया गया। साथ ही उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इसी प्रकार जनसुनवाई में प्राप्त एक अन्य आवेदन पर ग्राम सोमकुवा निवासी मीरा रावत को सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन स्वीकृत की गई। वहीं नाथी वेस्ता की वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में जांच कर यह पाया गया कि फरवरी 2026 तक पेंशन राशि जमा हो चुकी है तथा मार्च से जुलाई 2026 तक की राशि बैंक स्तर पर लंबित होने के कारण शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई प्रचलन में है।

वहीं गत दिवस की जनसुनवाई में निजी एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल की कक्षा तीसरी की छात्रा मुबस्सीरा अजमेरी के पिता श्री अब्दुल सलाम अजमेरी ने फीस बकाया होने के कारण विद्यालय द्वारा एसएलसी (टीसी) जारी नहीं किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं विद्यालय प्रबंधन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय द्वारा छात्रा की एसएलसी जारी कर दी गई, जिससे उसके शासकीय विद्यालय में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। आवेदन के त्वरित निराकरण पर परिवारजनों ने कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के प्रति आभार व्यक्त किया। कलेक्टर नीतू माथुर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रतिबद्ध है।

जनसहयोग से नर्मदा बैकवाटर में बना प्रदेश का पहला पक्का घाट

माही की गूंज, धार।

नर्मदा तट पर आस्था, जनसहयोग और श्रमदान की शक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने विकास की नई इबारत लिख दी। धार जिले की कुक्षी तहसील स्थित पवित्र कोटेश्वर तीर्थ के समीप सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में महज 54 घंटे में लगभग 54 लाख रुपये की लागत से 54 सीढ़ियों और छह चबूतरों वाला प्रदेश का पहला सीमेंट का पक्का बैकवाटर घाट तैयार कर दिया गया। वर्षों से बैकवाटर के कारण स्नान और धार्मिक गतिविधियों में आने वाली परेशानी अब इस घाट के निर्माण से काफी हद तक दूर हो जाएगी।

वर्ष 2017 में सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद कोटेश्वर तीर्थ का जलस्तर 131 मीटर पहुंचते ही तीर्थ तक जाने वाला मार्ग जलमग्न हो जाता है। इससे पर्व स्नान, धार्मिक आयोजन और नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था। पिछले लगभग 10 वर्षों से श्रद्धालु तीर्थ से करीब एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे बैकवाटर क्षेत्र में बिना घाट और गंदगी के बीच स्नान करने को मजबूर थे।

भूमिपूजन से शुरू हुआ जनसहयोग अभियान

कोटेश्वर नर्मदा बहुउद्देशीय सेवा संस्थान ने 14 जुलाई को कोठड़ा में भूमिपूजन कर घाट निर्माण का संकल्प लिया। 15 से 21 जुलाई के बीच 12 हजार 600 ट्राली भराव कर 128 मीटर से 139 मीटर तक मजबूत आधार तैयार किया गया। साथ ही 33 हजार वर्गफीट खोदाई कर 11 किसानों की सिंचाई और पेयजल पाइपलाइन को भी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया।

54 घंटे में तैयार हुआ 230 फीट लंबा घाट

28 जुलाई से तीन अगस्त तक प्रतिदिन सुबह नौ से शाम छह बजे तक संस्था के सदस्यों तथा देशवालिया, कड़माल, भवरिया, कोठड़ा, कोलगांव, निसरपुर और धूलसर सहित आसपास के गांवों के करीब 30 समाजसेवियों ने श्रमदान और मशीनों की सहायता से लगातार कार्य किया। सामूहिक प्रयास से 100 फीट चौड़े और 230 फीट लंबे घाट में 54 सीढ़ियां और छह चबूतरे तैयार किए गए। यह घाट श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक स्नान स्थल उपलब्ध कराएगा। वहीं इस घाट से कोटेश्वर तीर्थ बैकवाटर में जलमग्न होने पर मंदिरों के शिखर दर्शन भी किए जा सकेंगे।

अभी पहला चरण पूरा, आगे बनेगा भव्य घाट

संस्थान अध्यक्ष मोहनभाई पाटीदार ने बताया कि अभी घाट निर्माण का पहला चरण पूरा हुआ है और कुल लागत का लगभग 10 प्रतिशत दान ही प्राप्त हुआ है। आगामी चरण में इस घाट से जोड़ते हुए दोनों दिशाओं में 500 फीट चौड़ा और 230 फीट लंबाई का कुल घाट बनाया जाएगा। साथ ही आठ एकड़ क्षेत्र में मुक्तिधाम, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था, बगीचा और मंदिर निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। इस पूरे प्रकल्प पर लगभग तीन करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होंगे, जो जनसहयोग से जुटाए जाएंगे।

कोटेश्वर नर्मदा बहुउद्देशीय सेवा संस्थान ने जनसहयोग के माध्यम से नर्मदा किनारे लगभग 54 किलोमीटर की परिधि में 11 घाट और मुक्तिधाम विकसित किए हैं। वर्ष 2012 में कोटेश्वर मुक्तिधाम, 2016 में कोटेश्वर तीर्थ घाट, 2019 में राजघाट घाट एवं मुक्तिधाम, 2020 में कोठड़ा मुक्तिधाम, 2022 में छोटी कसरावद घाट, 2024 में जागीरदारपुरा घाट तथा 2025 में बोधवाड़ा घाट का निर्माण कराया जा चुका है, जिस पर चार करोड़ 11 लाख जनसहयोग से जुटाए गए। वहीं वर्तमान में सेमलदा, वराहनगर, बड़ा बड़दा और चिड़िया संगम (टवलाई) घाटों का निर्माण कार्य भी जनसहयोग से जारी है, जिनकी प्रस्तावित कुल लागत पांच करोड़ 11 लाख रुपये है।

शिक्षा में सुधार के लिए संसद से सड़क तक की गिरती राजनीति और स्थगित होती संसदीय कार्यवाही

माही की गूंज, झाबुआ।

संसद देश का कोई सामान्य भवन नहीं, यह भारत की आकांक्षा विश्वास, और समर्पण का केंद्र है, जहां भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व उनके चुने हुए सांसद प्रतिनिधि के रुप में करते हैं। लोकतंत्र की धूरी राज्यसभा और लोकसभा है, स्तंभ के रुप में पक्ष और विपक्ष है, संवाद और प्रतिवाद के माध्यम से भारत के नवनिर्माण का स्वरुप तैयार किया जाता है, और संसद में बैठकर सांसद, द्वारा समाज के प्रत्येक पायदान पर खड़े व्यक्ति के हितों की चिंताकर उनके जीवन स्तर में सुगमता लाने के लिए नीतियां बनाई और सुधारी जाती है, परंतु विपक्ष मनभेद कर शत्रुता के चरम पर जाकर देश में अपनी हार का बदला संसद को बाधित करके लेना चाहता है।

भारत देश को विकसित बनने का लक्ष्य अब 21 वर्ष दूर है, यह समय बताएगा कि, 2047 तक भारत विकसित देशों जैसा बन पाएगा या नहीं, किंतु वर्तमान में यह देखा जा सकता है कि, किसी देश को विकसित बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बुनियादी ढ़ाचे का निर्माण किस तरह से हो रहा है। संसद देश का वह महत्वपूर्ण भूभाग है जहां पर देश को सही दिशा में ले जाने के लिए नए विचारों से नए नियमों, और कानूनो का निर्माण किया जाता है, और वर्तमान में संसद की कार्यवाही प्रतिदिन विपक्ष के विरोध और हंगामों के कारण स्थगित की जा रही है। विपक्ष का हट देश के महत्वपूर्ण समय को हंगामा करते हुए नष्ट कर रहा है। जबकि विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए तथ्यों के साथ संसद के मानसून सत्र में कानून और विधेयकों पर बहस करना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर, हिंसा प्रदर्शन करने वालों ने देश के युवाओं में भ्रम पैदा करते हुए विपक्ष और भारत विरोधी शक्तियों ने छात्रों के नाम पर अपने स्वार्थ की रोटिया सेंकी, और वर्तमान में संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में शोर-शराबे के बीच संसदीय चर्चा के गिरते स्तर का प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष को जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए उसके लिए सड़क की राजनीति करना कितना उचित है यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर स्वयं विपक्ष के पास भी नहीं हो सकता है। देश में पेपर लीक होना एक गंभीर मामला है जिस पर आंदोलन में छात्रों ने अपनी मांग सरकार से मनवा ली लेकिन क्या उससे शिक्षा जगत में सुधार होना शुरु हो गया, नहीं हुआ और न ही इस तरह के आंदोलन या अपनी मांगे मनवा लेने से किसी प्रकार का कोई सुधार हो जाएगा।

जिस तरह विपक्ष आंदोलन में छात्रों पर अत्याचार की कहानी गढ़ते हुए, सड़क पर आकर अमीत शाह को संसद में आकर उत्तर प्रस्तुत करने की जीद पर उतरकर संसदीय कार्यवाही नहीं बढ़ने की धमकी देते हुए छात्र हित की लंगड़ी लड़ाई दिखा रहा है उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि, विपक्ष चाहता ही नहीं है कि, किसी भी तरह लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाए और वह पारित हो।

विपक्ष की अपनी एक गंभीरता होती है, विपक्ष का कार्य सिर्फ विरोध का नहीं होता है न ही हंगामा कर अपनी मर्यादा को धूमिल करते हुए अपने ही देश के उस महत्वपूर्ण समय को नष्ट करने का अधिकार होता है, अपितु विपक्ष सत्ता पक्ष को उसके द्वारा किये गए कार्यों की उन गलती को दर्शाता है जिसके कारण सरकार हानि में न आए और देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ का समान स्वरुप मिले, वहीं देश में स्वार्थ और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की धूरी पर कार्य संपन्न किया जाए। किंतु संसदीय कार्यकाल में विपक्ष ने अपने स्वरुप को ही बदल डाला, सड़क की राजनीति को लोकतंत्र की नीति बनाने की चेष्टा में बात-बात पर मंत्री के त्यागपत्र की मांग करके अपनी मर्यादा को भंग कर रहा है।

यदि संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है तो उसकी मर्यादा उसकी शुचिता और उसके प्रति शुद्ध आचरण की जिम्मेदारी सदन के सदस्यों की ही होती है, जिसे सड़क पर उछाला नहीं जाता। बीते शीतकालिन सत्र में भी विपक्ष द्वारा भयंकर हंगामा किया गया था। उस समय जब संविधान पर सतही वार्ता और विचार पर दोनों पक्ष सहमत हुए थे तो विपक्ष को विरोध के स्वर में आरोप के आगे पहुंचकर, लांछन लगाने और शोरगुल की सीमा को लांघते हुए धक्का मुक्की करते सदन की गरिमा का क्षरण किया था। उसके इस कृत्य से समाज को संविधान के संबंध में कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ या राष्ट्र विकास में कौन से नए चरण सम्मिलीत किए गए। कांग्रेस के राहुल गांधी संविधान को खतरे में बताकर देश की जनता में भय का भूत फैलाते हुए नागरिको को बरगलाते रहे परंतु उसमें कितनी सच्चाई थी उसे साबित नहीं कर पाए फिर भी शीतकालिन सत्र में संविधान पर चर्चा कर बताने का बहुत अच्छा मौका था परंतु आरोप की आड़ में राहुल गांधी स्वयं को और अपनी पार्टी की कमियों को छुपा भी नही पाए और सियासत में गिरावट के स्तर पर लाकर अपने पक्षधारो को खड़ा भी कर लिया।

प्रत्येक व्यक्ति के लिए जंतर-मंतर का छात्रों द्वारा किया आंदोलन आत्ममंथन और आत्मचिंतन का विषय है, उसी के बाद से देश में हर तरफ शिक्षा के स्तर में सुधार की मांग उठी। देश के स्कूलों कॉलेज की खराब स्थिति पर चिंतन किया गया, मगर क्या विपक्ष ने या धरना देने वाले छात्रों के सरदारों ने शिक्षा में सुधार कैसे किया जाना चाहिए उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर कोई विशेष राय या कोई आदर्श विचार प्रस्तुत किया... बिल्कूल भी नहीं किया... विपक्ष सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को भ्रमित करते हुए संसदीय कार्यवाही में विघ्न डालकर समय बर्बाद करना चाहता है जिससे सरकार किसी नए सुधार न कर पाए और स्वार्थी विपक्ष फिर से सरकार पर जनहित के मुद्दो से भटकने का आरोप लगा पाए।

रिंकेश बैरागी

हालांकि, देश की समुचे शिक्षा जगत में परिवर्तन लाना है तो सहर्ष और सामान्य सा एक नियम सरकार बना दे कि हर सरकारी वेतन पाने वाला व्यक्ति जिसमें विधायक, सांसद भी सम्मिलित है वह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही शिक्षित करेगा तब सुधार स्वतः ही शुरु होने लग जाएगा, और ऐसा सुधार होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी।

पेपर लीक और परिक्षाओं में नकल करना समाज का चारित्रिक और नेतिक पतन है। सरकार समाज के इस चारित्रिक और नेतिक पतन को रोकने उसे जड़ से समाप्त करने का कोई सहज, सरल उपाय लाना चाहती है तब उसे उसकी गहराई में जाकर गंभीरता से समझना पड़ेगा, जिसके उत्तर में सरकार को देश में भ्रष्टाचार के भंयकर बड़े रुप को देखकर मिलेगा। अब सरकार को समाज के नेतिक पतन जाने से रोकना है तो उसे तंत्र में घुल चूके भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा और यह नियम में कठोरता और दण्ड में सख्ती लाने से ही होगा।

नींव से ही भ्रष्टाचार

मामला: 6 करोड़ में बनने वाले सांदीपनि छात्रावास का

माही की गूंज, खवासा। सुनिल सोलंकी

डबल इंजन की सरकार और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार में नित नए भ्रष्टाचार को गढ़ने में अपना एक मुकाम हासिल किया जाता रहा है। ऐसे में किसी निर्माण कार्य में बिना भ्रष्टाचार व अनियमित्ता के कोई कार्य हो सके यह अब किसी को संभव नहीं लगता है।

बात करें सांदीपनि स्कूल व उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनने वाले छात्रावास की तो यह सभी को विदीत है कि, शिवराज सरकार ने इसकी नींव सीएम राइज स्कूल के नाम से गढ़ी थीं वहीं भाजपा के ही मोहन सरकार ने इसका नाम बदलकर सांदीपनि स्कूल रख दिया। नाम बदलने के साथ देखने में आ रहा है कि, सीएम राइज स्कूल की जो व्यवस्था बच्चों को पढ़ने हेतु मिलने थी वह नाम बदलने के साथ ही सभी परिवर्तित हो गया। सीएम राइज स्कूल की नींव गढ़ते समय आधुनिक एवं प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर 15 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले बच्चों को बसों के माध्यम से लाया ले जाया जाएगा। लेकिन झाबुआ जिले में स्कूल के नाम बदलने के साथ ही इस व्यवस्था में ही परिवर्तन कर दिया और आज तक पहले क्रम में बनी उक्त सीएम राइस (सांदीपनि) स्कूल का काम पूर्ण हो चुका और दूसरे क्रम की बनने वाली सूची भी जारी हो चुकी हैं। लेकिन जो उक्त स्कूले बनी उसमें अब तक बसों की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

कुछ जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, मोहन सरकार ने ट्राइबल जिलों में बसों की सुविधा नहीं देते हुए शिक्षा विभाग के माध्यम से सांदीपनि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास बनाने का विचार कर बसो की व्यवस्था को कैंसल कर दिया गया है।

इसी कड़ी में खवासा में स्टेडियम के पास 100 लड़कियों व 100 लड़कों के अलग-अलग दो कुल 200 सीटर जिसकी लागत करीब 6 करोड़ है छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। उक्त छात्रावास 200 छात्र-छात्राओं के लिए एक अच्छी एवं बड़ी उपलब्धि जरूर माना जा सकता है। लेकिन खवासा सांदीपनि स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक करीब 1000 बच्चों से अधिक के पढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में 200 बच्चों के अलावा बाकी बचे हुए बच्चों का क्या...? जिन्हें तो अपने घर से बिना बस के ही पुरानी व्यवस्था अनुसार ही पैदल या फिर यातायात को ताक में रख ओवरलोड वाहनों में भेड़-बकरियों की तरह ही बैठ कर उक्त स्कूल में अध्यन हेतु आना-जाना है।

अनियमित्ता व भ्रष्टाचार की नींव के साथ सांदीपनि छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू।

वहीं बन रहे छात्रावास के बावजूद क्षेत्र वासियों की मांग है कि, जो व्यवस्था सीएम राइज स्कूल की नींव गढ़ते समय जो सुविधा देने की बात भाजपा सरकार ने की थी वह सभी सुविधाएं बसों के साथ मिलनी चाहिए।

निर्माणधिन छात्रावास की हकीकत

वही बन रहे उक्त 200 सीटर के छात्रावास के निर्माण की हकीकत जानना चाही तो सामने आया कि, वहा कालम हेतु की गई नींव खुदाई में ही अनियमितओं व भ्रष्टाचारों की नींव गणना शुरू कर दी गई। उक्त छात्रावास निर्माण का ठेका जिले के ही किसी अक्षय कटारिया की फर्म ने लिया है। तथा कटारिया ने किसी अन्य व्यक्ति को पेटी कांट्रेक्टर में अपना ठेका निर्माण हेतु दे दिया गया।

उक्त निर्माण कार्य के कंस्ट्रक्शन संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्ति बताते हैं कि, उक्त छात्रावास निर्माण स्टीमेंट व गाइडलाइन अनुसार कालम हेतु नींव खुदाई के साथ ही अनियमितता की जा रही है। कालम हेतु जो गड्ढे खोदे गए इसकी खुदाई कम की गई। वहीं बिम व कालम जो खड़े किए जा रहे उसमें अभी से छेद दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उक्त छात्रावास का पूरा निर्माण के दौरान की जाने वाली अनियमितताएं किस तरह की निम्न स्तर की होगी इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

जानकारी रखने वाला उक्त व्यक्ति बताता है कि, पीडब्ल्यूडी की शाखा पीआईयू के तहत किया जा रहा उक्त अनियमिताओं का कार्य कोई पहला नहीं है। पूर्व में क्षेत्र के नारेला में भी उक्त पीआईयू एजेंसी की देखरेख में ही छात्रावास बनाया गया था, जहां छात्रावास निर्माण के दौरान ही भ्रष्टाचार व अनियमिताओं के चलते दीवार बीच सेंटर में से फूटने की नौबत आ चुकी थी। जो मामला भी समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर हुआ और मरम्मत करवा कर लीपा-पोती कर दी गई थी।

इसी तर्ज पर खवासा में 6 करोड़ के करीब बनने वाले यह दोनों छात्रावास आम जनता की अनदेखी के चलते सिस्टम की भेंट चढ़ अनियमित्ता व भ्रष्टाचार के साथ यह निर्माण करने की मनसा ठेकेदार द्वारा की जा रही है। जिसका उदाहरण नींव खुदाई के साथ ही की जा रही अनियमितता व भ्रष्टाचार के साथ देखा जा सकता है। इसलिए सिस्टम को मुंहजोर जवाब व स्टीमेंट व गाइडलाइन अनुसार यह निर्माण कार्य सही से हो इसके लिए क्षेत्र के पत्रकारों के साथ आम जनता को भी सजग रहना आवश्यक होगा। तभी क्षेत्र के नोनिहालों के भविष्य की नींव मजबूत रखी जा सकती है।

स्वयं-भू माता लोक को शिव-मोहन की विकास दृष्टि चाहिए

घोषणाओं से नहीं, अब धरातल पर दिखे आस्था का सम्मान

माही की गूंज, थांदला। मुकेश भट्ट

राजनीति में घोषणाएं करना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना ही सुशासन की असली कसौटी है। झाबुआ जिले के थांदला के समीप स्थित स्वयं-भू माता मंदिर इसका एक जीवंत उदाहरण है। मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान की त्रिवेणी सीमा पर स्थित यह मंदिर लाखों आदिवासी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आदिवासी समाज इसे अपनी कुलदेवी के रूप में पूजता है और वर्षभर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साथ ही वर्ष में एक बार यहां मेले का भव्य आयोजन होता है। इतनी बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान होने के बावजूद यह स्थल आज भी मूलभूत सुविधाओं और समग्र विकास की प्रतीक्षा में है।

विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं-भू माता मंदिर परिसर में आयोजित सभा से इस स्थान को स्वयं-भू माता लोक के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। उस समय यह घोषणा केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि आदिवासी आस्था के सम्मान का प्रतीक मानी गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि यहां धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय विकास का नया अध्याय शुरू होगा।

समय बदला, सरकार बदली और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डॉ. मोहन यादव आ गए। स्वाभाविक रूप से क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि, पूर्व मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण घोषणा को आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया।

31 जुलाई को थांदला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक कलसिंह भाबर ने मंच से मुख्यमंत्री के समक्ष स्वयं-भू माता लोक बनाए जाने की मांग दोहराई। यह अवसर था जब सरकार इस अधूरी घोषणा को नई गति दे सकती थी, लेकिन अनेक विकास कार्यों की घोषणाओं के बीच स्वयं-भू माता लोक का नाम फिर छूट गया। मंच पर मांग उठी, तालियां भी बजीं, लेकिन घोषणा नहीं हुई।

प्रश्न यह है कि, यदि महाकाल लोक, ओरछा, चित्रकूट और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार गंभीर हो सकती है, तो आदिवासी समाज की इतनी बड़ी आस्था के केंद्र को वह महत्व क्यों नहीं मिल रहा, जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा है...?

स्वयं-भू माता लोक केवल एक मंदिर परियोजना नहीं होगी। यह आदिवासी संस्कृति, लोक परंपरा और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकती है। इससे क्षेत्र में सड़क, पार्किंग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, यात्री सुविधाएं, स्थानीय रोजगार और व्यापार के नए अवसर विकसित होंगे। इससे थांदला सहित पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

जनता यह भी जानना चाहती है कि, क्या चुनावी मंचों से की गई घोषणाएं केवल चुनाव तक सीमित रहती हैं...? यदि नहीं, तो स्वयं-भू माता लोक की घोषणा आज तक अमल में क्यों नहीं आई...? सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता के सामने किए गए वादे सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी होते हैं। अब सरकारों को भी यह साबित करना होगा कि, उनकी विकास दृष्टि केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि दूरस्थ अंचलों की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत तक भी पहुंचती है।

स्वयं-भू माता लोक अब केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की अपेक्षा है। शिवराज ने सपना दिखाया था, अब 'मोहन' सरकार की दृष्टि से यह सपना साकार होना चाहिए। क्योंकि आस्था को आश्वासन नहीं, विकास चाहिए।

अटल बस्ती में हुई हत्या को लेकर आक्रोश, आरोपियों पर पुलिस ने किया इनाम घोषित

मुख्य आरोपी जनपद अध्यक्ष का पति एवं भाजपा नेता, पेटलावद-सरदारपुर में ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद।

एक अगस्त को पेटलावद में एक महिला के घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट किए जाने और महिला को बचाने आए व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या व मारपीट करने का आरोप धार जिले की सरदारपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति व भाजपा नेता देवा सिंगाड़ व उसके साथियों पर है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी देवा सिंगाड़ सहित अन्य पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल महिला ने पुलिस को बताया है कि, वो शनिवार देर रात अपने घर में थी उसके साथ उसका दोस्त हरिराम सिरवी (55) निवासी धुलेट भी था। देर रात करीब 5 लोगों ने उनके घर में जबरन घुसने की कोशिश की। आगे का दरवाजा नहीं खोलने पर आरोपी पीछे के रास्ते से घर के अंदर आ गए और अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में रखी लकड़ी और मोगरी से उस पर व बीच-बचाव कर रहे हरिराम पर ताबड़तोड़ वार किए। महिला ओर पुरुष दोनों को निर्वस्त्र कर मारा गया ओर दोनों पर जबरन संबंध बनाने का दबाव तक डाला गया। पूरे घटनाक्रम के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिससे हत्या को अंजाम देने वाले अपराधियों की घृणित मानसिकता का पता चलता है। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने पुलिस को बताया कि, मुख्य आरोपी देवा पिता थावरिया सिंगाड़ के साथ वह करीब 14 साल से संपर्क में थी। हालांकि पिछले करीब एक साल से आरोपी देवा से पूरी तरह दूरी बना ली थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था जिसने शनिवार रात को हिंसक रूप ले लिया। महिला के मुताबिक वो और हरिराम 31 जुलाई को उज्जैन दर्शन के लिए गए थे और 1 अगस्त की शाम को ही वापस लौटे थे। महिला का देवा से दूर होना और हरिराम का उसका सहयोगी बनना आरोपी को रास नहीं आया।

आरोपी ने परिजन को धमकाया

मृतक हरिराम के पुत्र राजू ने बताया कि, शनिवार रात आरोपी उनके धुलेट स्थित घर पर भी आए थे और गाली-गलौज करने के बाद चले गए। इसके बाद रविवार सुबह करीब 5 बजे पेटलावद अस्पताल से फोन आया कि, उनके पिता की हालत गंभीर है। इसके बाद वे वापस पेटलावद पहुंचे। आरोपियों की दबंगई का आलम यह था कि, सुबह होते ही दोबारा हरिराम के घर पहुंचे और परिजन को धमकाया।

घायल महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी देवा पिता थावरिया सिंगाड़ और अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देवा सिंगाड़ सरदारपुर जनपद अध्यक्ष का पति है और बताया जा रहा है कि भाजपा नेता है।

- मृतक हरिराम सिरवी और अस्पताल में भर्ती घायल महिला।

सिरवी व सर्व समाज ने राज्यपाल और सीएम को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों के लिए फांसी की मांग

1 अगस्त 2026 की रात्रि को हुई एक निर्मम हत्या के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय सिरवी समाज और सर्व समाज ने कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए सोमवार को पेटलावद ओर मंगलवार को जिला प्रशासन को महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके पहले पेटलावद में बड़ी संख्या में समाजजन नारेबाजी करते हुए आईं माता मंदिर से पुराना बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे।

ज्ञापन में बताया गया कि, धार जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत राजगढ़ निवासी आरोपी देवा पिता थावरिया सिंगाड और उसके साथियों ने पेटलावद की अटल बस्ती में आकर हरिराम पिता गोमा जी पर लाठी-डंडों से कातिलाना हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में हरिराम को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

इस जघन्य हत्याकांड से आक्रोशित समाजजनों ने प्रशासन के समक्ष आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं जैसे धारा 103 (हत्या), धारा 109 (हत्या का प्रयास), तथा धारा 191 व 190 (दंगा एवं आपराधिक षड्यंत्र) के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग की है।

इसके साथ ही, मुख्य आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगालते हुए उस पर एनएसए (एनएसए) और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने, उसकी अवैध संपत्तियों की जांच कर उन्हें जप्त करने, मृतक एवं घायल महिला के वीडियो बयानों व पीएम रिपोर्ट को सुरक्षित रखने तथा पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की पुरजोर मांग उठाई गई।

इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन की प्रतियां गृहमंत्री, पुलिस महानिदेशक, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी और थाना प्रभारी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं। न्याय की इस मांग के दौरान बड़ी संख्या में सिरवी समाज एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। उधर घटना की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को एसपी देवेन्द्र पाटीदार घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का संज्ञान लिया। एसपी पाटीदार ने मामले में कड़ी कार्यवाही करने ओर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसपी पाटीदार ने दस हजार का इनाम तक घोषित कर दिया।

असल मालिकों की जगह किरायेदारों से लेस अटल बस्ती को लेकर फिर खड़े हुए सवाल

अटल बस्ती फिर सवालों के घेरे में

सरकार ने गरीब वर्ग को पक्का मकान देने की योजना पर काम करते हुए लगभग दो सौ से ज्यादा पक्के मकान बना कर नगर परिषद के माध्यम से गरीब वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को आवंटित किए थे। लेकिन आवंटन के बाद से इसमें फर्जीवाड़े की बात सामने आई ओर कई पूंजी पति और अपात्रों को मकान वितरण करने की बात सामने आई। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री स्तर पर हुई, नगर के युवा विक्रम कटारा ने मुख्यमंत्री तक शिकायत की जिसकी जांच हुई लेकिन अपनी गर्दन बचाने के लिए हर बार जांच में घुमा फिरा कर आवंटन को सही बताया। वास्तविक में मामला पूरा फर्जी आवटन से जुड़ा है क्योंकि ज्यादातर मकान आज भी या तो बंद पड़े हैं या फिर उसमें किराएदार रह रहे हैं। किराएदारों में ज्यादातर लोग बाहरी है, जिसका नगर में कोई रिकॉड नहीं है, जिस मकान में वारदात हुई वो मकान भी किराए का होना बताया जा रहा है और मरने वाला व्यक्ति ओर घायल महिला भी बाहरी हैं। उसे मारने वाले भी धार जिले से आए थे। अटल बस्ती से लगातार अवैध व्यापार ओर नशे के कारोबार अनैतिक कार्यों, सहित बड़े वाद विवाद की खबरे आती रही हैं। हर बार शिकायत के बाद जांच होती है, किरायेदारों की सूची तैयार होती है कार्रवाई की धमकी के बाद वसूली ओर मामला फिर से फाइलों में दब जाता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422